>

Title: Further discussion on the statement made by the Minister of Defence on 06.08.13 regarding Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of Natural Disaster in Uttarakhand raised by Smt. Sushma Swaraj on the 30th August, 2013.

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Discussion under Rule 193.

Shrimati Sushma Swaraj.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order please.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We are going to have a very important discussion. Please have silence in the House.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order please.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति महोदय, बहुत पीड़ा के साथ मैं उत्तराखंड त्रासदी के बारे में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमने सोचा था कि जब पांच अगस्त को मानसून सत्र शुरू हुआ, हम सत्र के पहले दिन ही इस चर्चा को शुरू करते, क्योंकि दो सत्रों के अंतराल में यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई, जो देश को झेलनी पड़ी। इसलिए संवेदना का तकाजा था कि सत्र के प्रारम्भ में ही इसकी चर्चा होती, लेकिन किसी न किसी कारण से यह चर्चा टलती रही और आज मानसून सत्र के एक महीने बाद, क्योंकि पांच अगस्त को मानसून सत्र शुरू हुआ था और आज चार सितम्बर है और वह भी शाम के छह बजे चर्चा शुरू हो रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि कम से कम सत्र की समाप्ति से पहले यह चर्चा हो रही है। अगर चर्चा किए बिना सत्र समाप्त हो जाता, तो मेरे मन में भी पछतावा रहता और उन पीड़ितों को भी लगता कि हमारी पीड़ा का बखान किसी ने नहीं किया।

सभापति जी, प्राकृतिक आपदाएं तो इस देश में पहले भी आई हैं। अगर मैं केवल पिछले वर्षों का आकलन करूं, तो बड़ी आपदाओं के रूप में गिन सकती हूं, वह राज्य जहां से आप आते हैं उड़ीसा में झंझावात आया, गुजरात में भूकम्प आया और दक्षिण में सूनामी आई। ये ऐसी आपदाएं थीं, जिन्होंने क्षण भर में लोगों को लाख से खाक कर दिया। घर-बार भी छीन लिया और रोजगार भी छीन लिया। लेकिन उत्तराखंड में जो आपदा आई, वह इन आपदाओं से दो मायने में अलग है। एक तो इस मायने में अलग है कि उड़ीसा, गुजरात और दक्षिण का सुनामी इनका भौगोलिक व्यास सीमित था। झंझावात और भूकम्प एक-एक राज्य तक सीमित था। सूनामी दक्षिण के तीन-चार राज्यों को प्रभावित कर रहा था। लेकिन उत्तराखंड की आपदा का व्यास पूरे देश में फैला था। पूरे देश के लगभग सभी राज्यों के लोग इसमें प्रभावित हुए, यह पहला अंतर है। दूसरा बड़ा अंतर है कि इस आपदा में हमने पराकाष्ठाएं देखीं। कौन-कौन सी पराकाष्ठाएं देखीं, अगर एक तरफ प्रकृति के प्रकोप की पराकाष्ठा देखी, तो दूसरी तरफ लोगों की लाचारी की भी पराकाष्ठा देखी। अगर एक तरफ सेना और अर्द्धसैनिक बलों के शौर्य की पराकाष्ठा देखी, तो दूसरी तरफ एयरफोर्स के पायलटों के धैर्य की भी पराकाष्ठा देखी। अगर एक तरफ राज्य सरकार की अकर्मण्यता की पराकाष्ठा देखी, तो दूसरी तरफ लूटेरों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी देखी। इन पराकाष्ठाओं के कारण यह त्रासदी न भूतो न भविष्यतः की श्रेणी में आकर खड़ी हुई।

18.00 hrs.

कुछ दिन के बाद जब यह सत्र शुरु हुआ, रक्षा मंत्री जी ने राहत और पुनर्वास से संबंधित एक वक्तव्य इस सदन में रखा था। मैं कहना चाहती हूं, आज गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। गृह मंत्री जी तब अस्वस्थ थे। वह नहीं आ सके थे। गृह मंत्री जी, पता नहीं आपने वह वक्तव्य पढ़ा या नहीं। वह वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : It is 6 o'clock now. If the House agrees, we may take up the RTI Bill after the discussion under 193. Now, it is extended till the discussion is over.

...(*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: No. We should take it up tomorrow....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

...(*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): You have to take the sense of the House. ...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, इस चर्चा को पहले कर लें।...(व्यवधान) इसे स्कटल न करें। उसके बाद देखेंगे। जो हाउस का मूड होगा, उस तरीके से करेंगे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: After the discussion is over, next item will be taken up.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं गृह मंत्री जी को बता रही थी कि पता नहीं उन्होंने वह वक्तव्य देखा या नहीं देखा। वह वक्तव्य असत्य का पुलिंदा था। वह निराधार तथ्यों पर आधारित था। उस वक्तव्य में रक्षा मंत्री जी ने कहा:

> "Highly commendable work was done by the State Government and the Central Ministries and agencies in this long hour of crisis."

जहां तक सेन्ट्रल एजेंसी का सवाल है, मैं यहां खड़े होकर सेना, एयर फोर्स, अर्ध-सैनिक बलों, आईटीबीपी और एनडीआरएन के जवानों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए जान हथेली पर रखकर हजारों लोगों की जिन्दगियां बचाई। आज इस सदन में खड़े होकर समूचे राष्ट्र की तरफ से मैं उनका अभिनन्दन करती हूं और अपनी तथा सदन की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं तथा जो शहीद हो गए, उनको मैं अपना प्रणाम-निवेदन करती हूं। उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। लेकिन जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है, गृह मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार पूरी तरह से अयोग्य और अक्षम साबित हुई। रक्षा मंत्री कहते हैं:

> "The State Government immediately initiated necessary steps for rescue and relief as the first responder."

सच्चाई यह है कि 16 तारीख की सुबह यह आपदा आई और 18 तारीख की रात तक न राज्य सरकार को, न केन्द्र सरकार को, न मीडिया को और न देश को इसकी गंभीरता का पता था। 18 तारीख की रात को उत्तराखंड के नेता, प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, यह केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई। मैंने कहा क्या! उन्होंने कहा कि केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई है। सारे होटल, सारी धर्मशालाएं, सारी दुकानें बह गई हैं। उन्होंने कहा कि 5000 खच्चर और खच्चरों के हैंडलर्स सब बह गए हैं, लेकिन अभी कोई राहत कार्य शुरु नहीं हुआ है। मैंने कहा कि आप फोन रखो। मैं अभी गृह मंत्री जी से बात करती हूं। शिंदे जी यहां बैठे हैं। मैंने उनका फोन बंद किया और शिंदे जी को फोन लगाया और मैंने कहा कि उत्तराखंड के नेता, प्रतिपक्ष का मुझे फोन आया है और उन्होंने मुझे यह बात बताई है। इस पर शिंदे जी ने कहा कि मैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के सम्पर्क में हूं। इतना ज्यादा भीषण कुछ नहीं है। 10-12 लोगों की मौत हुई है। मैंने आज सेना के 12 हैलीकॉप्टर मंगा लिए हैं और 12 कल मंगा लूंगा। शिंदे जी, आपने कहा था, हूबहू जो बात आपने कही थी, वर्बेटिम मैंने यहां रखी है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, मामला इससे कहीं बड़ा है इसलिए केवल 12 हैलीकॉप्टरों से काम नहीं चलेगा, सैंकड़ो हैलीकॉप्टरों का काम है, आप सेना को बुलाइए, केवल सेना के हैलीकॉप्टर आएं। इन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूं। मैंने उसी समय ट्वीट किया, एसओएस फ्रोम उत्तराखंड और उसमें सारी बातें लिखी कि हजारों लोग मर गए हैं, मेरी अभी गृह मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वे इस बारे में पूरा काम करेंगे। मुझे अगले दिन लंदन जाना था, दो बजे की एयर इंडिया से फ्लाइट बुक थी। सबसे पहले मैंने फ्लाइट रद्द की, यात्रा रद्द की। मैंने अजय भट्ट को फोन किया और कहा कि मेरी शिंदे जी से बात हो गई है और कल से कुछ शुरु होगा। मैं कहना चाहती हूं कि रक्षा मंत्री जिसे फर्स्ट रिस्पांडर कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, 18 तारीख को पहला हैलीकॉप्टर सेना का उड़ा था लेकिन 19 तारीख को विधिवत बचाव कार्य शुरु किया गया जबकि घटना 16 तारीख को सुबह सात बजे की थी।

महोदय, अगर इमीडिएटली का मतलब सात घंटे से ज्यादा होता है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। इमीडिएटली का हिंदी में मतलब तत्काल है, तुंत है। मैं आज यहां जिम्मेदारी से खड़े होकर कह रही हूं कि 18 तारीख को सेना का पहला हैलीकॉप्टर उड़ा और 19 तारीख से विधिवत बचाव कार्य शुरु हुआ। आप हैरान होंगे, जिस राज्य सरकार की रक्षा मंत्री पीठ थपथपा रहे थे, 29 दिन के बाद 15 जून को उन्होंने उन चार जगह पर अतिरिक्त चार जिलाधिकारी लगाए जो आपदाग्रस्त थे। मेरे पास शासनादेश की प्रतियां हैं - 15 जून, श्री सचिन कुर्वे को गुप्तकाशी से केदारनाथ क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी, श्रीधर बाबू अहानगी को भटवारी, हरसिल और गंगोत्री क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी, डॉ. वी. शमरगन को गोचर से ठराली ग्वालदाम क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी और डॉ. दीपक रावत को मुनियारी एवं धारचूला क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी। ये चारों शासनादेश 15 जून के मेरे पास हैं, अगर आप अनुमति देंगे या चाहेंगे तो मैं सभापटल पर रख दूंगी। 29 दिन के बाद चारों जगह पर जिलाधिकारी लगाए गए, यह राज्य सरकार का रिस्पांस है।

सभापति जी, 40 दिन के बाद इन क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। 29 दिन के बाद अधिकारी लगे और 40 दिन बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। 30 दिन तक शव नहीं निकाले गए। 30 दिन बाद शव निकाले गए और उन शवों की जो दुर्गति हुई, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं, कलेजा मुंह को आता है। वहां लुटेरों की बन आई और लुटेरों ने शवों की उंगलियां काटकर अंगूठियां निकाली। मृतक देहों के गहने उतार लिए। जब दाह संस्कार किया गया तो अधजले शव पड़े रह गए। वहां जिस समय लुटेरे ऐसा कर रहे थे उस समय गृह मंत्री जी, आपके जनाव सीएम साहब सर्किट हाउस में खड़े होकर गार्ड आफ ऑनर ले रहे थे। वे पुलिस वाले जिन्हें इलाके में लोगों की रक्षा करने के लिए, लुटेरे से उन शवों को बचाने के लिए होना चाहिए था, वे उस समय वहां उनको सलामी ठोक रहे थे। आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कमेन्डेबल काम किया। रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि कॉम्युनिकेशन सिस्टम तुंत बहाल कर दिया। मैं कहना चाहती हूं कि अगर तुंत कॉम्युनिकेशन सिस्टम बहाल कर दिया होता तो परिजन इतने बेबस और असहाय नहीं होते। जितने लाचार पीड़ित थे उससे ज्यादा असहाय और बेबस उनके परिजन थे। अगर कॉम्युनिकेशन सिस्टम बहाल हो जाता तो लोग फोन कर सकते थे, फोन करके घर के लोगों को बता सकते थे कि फिक्र मत करना हम फंसे जरूर हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। लेकिन कोई कॉम्युनिकेशन नहीं था, कोई फोन नहीं चल रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे बल्कि परिजनों को गलत खबरें दी जा रही थी। बहुत लोगों को कह दिया गया कि तुम्हारे लोग फलां हैलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वे अपने घरों से देहरादून के हैली पैड पर पहुंच गए। वे एक हैलीकॉप्टर उतरता वे देखते, दूसरा उतरता तो देखते, तीसरा उतरता तो देखते, चार-पांच हैलीकॉप्टर उतरने के बाद जब उन्हें परिजन नहीं मिले तो पता चला की गलत खबर चली गई थी, गलत सूचना चली गई थी।

The Defence Minister says,

> "Essential supplies like food, drinking water, medicines, kerosene oil, blankets, etc., were continuously provided by airdropping as well as land routes."

गृह मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जेसीबी थी, मगर डीजल नहीं था। बद्रीनाथ मंदिर समिति में रसद थी, वे खाना देना चाहते थे, मगर उनके पास गैस नहीं थी। गैस खत्म हो गई तो हमने कहा कि कैरोसिन भेज दो। लेकिन दो दिन तक कैरोसिन नहीं जा सका था। आप कौन सी असेंशियल सप्लाईज़ की बात कर रहे हैं? लोगों ने यहां से ट्रक के ट्रक भर कर भेजे। लेकिन हेलिपैड पर सामग्री पड़ी रही और लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। गुप्तकाशी के गोदाम में सामग्री सड़ रही थी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही थी। आप कौन सी बात करते हैं? कौन सी राज्य सरकार की बात करते हैं? वहां राज्य सरकार या प्रशासन का नामोनिशान तक नहीं था। आपने खुद जा कर वहां देखा और कहा कि तालमेल का आभाव है तो आपने केंद्र से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया और कहा कि यह जा कर ताल-मेल का काम करेगा। सेना कहती थी कि हमारे पास राज्य सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है। हमें तो जगहें भी नहीं पता कि हमको जाना कहां है? हैलिकॉप्टर क्रैश कर गया। उस दिन हमको लगा कि शायद अब कोई दूसरा हैलिकॉप्टर नहीं उड़ेगा। लोग डर जाएंगे। लेकिन मैंने कहा न कि मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को। उधर हैलिकॉप्टर क्रैश हुआ, 20 लोग मरे, 5 क्रू के लोग और 20 दूसरे लोग मरे। लेकिन माथे पर शिकन डाले बिना, दूसरा हैलिकॉप्टर तैयार हो कर के कैप्टंस चढ़ गए और वापस लोगों को निकालने के लिए लग गए। इसलिए मैंने कहा कि अगर अभिनंदन का पात्र कोई है कि तो सेना और एयरफोर्स के लोग हैं। लेकिन राज्य सरकार की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार इतनी नालायक और निकम्मी साबित हुई है कि मैं यहां खड़े हो कर कहना चाहती हूँ कि यही कारण था कि मैंने राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी।

सभापति जी, यह अनहोनी घटना नहीं है। जो ऐसे ही घट गई। यह ऐसी घटना है जो रोकी जा सकती थी। मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी थी कि 16 जून से वहां बारिश शुरू होगी। इसरो ने चेतावनी दी थी कि बादल फटेगा और इसलिए पहाड़ की यात्रा मना कर दो। मैं आज कहती हूँ कि अगर आपने यात्रियों को अलर्ट जारी किया होता, अगर ऋषिकेश, रूद्रप्रयाग और गौरीकुंड में आपने यात्रियों को कह दिया होता कि आप आगे मत आइए तो बीसियों हज़ार जानें बच सकती थीं। क्योंकि ऋषिकेश, गौरीकुंड, रूद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच में 20 हज़ार से ज्यादा लोग थे। जिनमें से एक भी नहीं बचा। उन सारी जिंदगियों को बचाया जा सकता था। लेकिन मेरा आरोप है कि न तो इस यात्रा की कोई पूर्व तैयारी थी और न ही इस हादसे के बाद कोई संवेदनशीलता थी और न बाद में राहत और पुनर्वास की कोई तत्परता थी।

मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकार आज तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दे सकी, आप उस सरकार की पीठ थपथपाते हैं, उसको आप शाबाशी देते हैं?

सभापति जी, आपदा प्रबंधन मंत्री ने 10 दिन के बाद कहा था कि मरने वालों का आंकड़ा 5 हज़ार तक पहुंचेगा। इनके अपने स्पीकर कुंजवाल ने कहा था कि मरने वालों की संख्या तो 10 हज़ार हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे कर कहा था कि 822 लोग मरे हैं। रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि 520 लोग मरे हैं। कहां 5 हज़ार, कहां 10 हज़ार, 822 और आ कर आंकड़ा 520 तक रूक गया। लापताओं की संख्या आप नहीं बता सके। आपको मालूम नहीं है कि कितने लोग लापता हुए। सभापति जी, हमारे यहां कहते हैं कि मरे का सबू आ जाता है, लापता का सबू नहीं आता है। जब आदमी मरे हुए का दाह

संस्कार कर लेता है तो लगता है कि व्यक्ति चला गया। लेकिन लापता के लिए हमेशा आंखें इंतज़ार करती रहती हैं। एक फिल्म का एक गीत है कि -

> " ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। "

हज़ारों पत्नियां आज भी अपने पतियों का इंतज़ार कर रही हैं। हज़ारों मातायें आपने बेटों का इंतज़ार कर रही हैं। हज़ारों बच्चे अपने माता-पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद किसी दिन दरवाज़े की घंटी बजेगी और हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमें अपना पति खड़ा मिलेगा, अपनी माँ खड़ी मिलेगी, अपना बच्चा खड़ा मिलेगा।

सभापति जी, ये आज तक लापता का आंकड़ा नहीं दे पाए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि क्या सूचना के इस युग में हम सही आंकड़ा भी नहीं दे सकते हैं? गृह मंत्री जी, मैं आपको कहती हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर आप देश के सारे थानों को एक सर्कुलर भेजें और उसको यह कहें कि आपके थाने के नीचे कितने लोग मरे हैं और कितने लोग लापता हैं, तो एक सही आंकड़ा तो आपके पास आ जाएगा। मैंने अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र का आंकड़ा मंगवाया। मेरे पास आंकड़ा आया, मेरे विदिशा जिले के 23 लोग मरे हैं, मेरे रायसेन जिले के 10 लोग और मेरे बुधनी में नसरूलागंज में 23 लोग मरे हैं, लापता हैं। आप हैरान होंगे कि बांयगोड़ी गांव के एक परिवार के सात लोग, रिठवाड़ गांव के एक परिवार के आठ लोग, एक-एक परिवार के आठ-आठ लोग, एक-एक परिवार के सात-सात लोग, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि कम से कम इन लोगों का सही आंकड़ा तो मंगवा लीजिए। आप राहत और पुनर्वास कैसे करेंगे? आप यहां बैठे घोषणायें कर रहे हैं कि हम साढ़े तीन-तीन लाख रूपए उनको देंगे, मगर देंगे कैसे, जब आपके पास पता नहीं होगा? मैं अपने सुझाव को पुनः दोहराती हूं कि केंद्र की तरफ से एक सर्कुलर सारे थानों को भेजिए और उन थानों से लापता और मृतकों की संख्या मंगवाइए, ताकि एक सही आंकड़ा आप लोगों के सामने रख सकें। 520 से लेकर 10 हजार तक का आंकड़ा, आपस में कहीं कोई मेल नहीं खाता है।

महोदय, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेज विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, यह उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों-खरबों रूपए खर्च करके विकास करते जाते हैं, प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाशलीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी, क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं, क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको, उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी-चोटी का जोर लगा रही थीं, उन धारी देवी को बचाने के लिए। वे एक-एक के घर जाती थीं, आड़वाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर, मुझे साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास गयी थीं, पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थीं। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर धारी देवी वहां से हटायी नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वह शिला हैं, जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे।

महोदय, आप जानते हैं कि यह मात्र संयोग नहीं है, मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूं, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुयीं, उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुयीं और इधर केदारनाथ में जलप्रलय आया। यह ऐसा जलप्रलय आया जो हजारों जिन्दगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है - "अपूज्यम् यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम् तुव्यतिक्रमा, त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम् मरणः भयः" अर्थात् जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां तीन चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। वहां की पूज्या, उत्तराखण्ड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और ये तीनों चीजें वहां आ गयीं। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यह जो विकास वर्सेज विनाश का प्रश्न है, यह आज वहां मुंह बांये खड़ा है। गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं, आप जानते हैं योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनन्दा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है। आज रेवती रमण सिंह जी यहां बैठे नहीं हैं, दो-दो बार चर्चा करायी है इस सदन में उन्होंने, हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं।

महोदय, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए माँ है। पता नहीं उस दिन आप सेंट्रल हॉल में थे या नहीं, मुझे आश्चर्य निश्चित हर्ष हुआ था, इतना हर्षित हुआ था मन, जापान के प्रधानमंत्री जी ने केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को सम्बोधित करते हुए गंगा जी का नाम लिया था तो उन्होंने गंगा मैया कहा था। वे लोग हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं, वे हमारी आस्था की कद्र करते हैं। वे गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन गंगा जी को जो लोग सुंग में डालना चाह रहे हैं, उन उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएँ सहनी पड़ रही हैं जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर यह कहना चाहती हूँ कि धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिये। मैं यहाँ से मांग करती हूँ कि गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिये। जितना मर्ज़ी पैसा उन पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा राहत और पुनर्वास पर खर्च होने वाला है, वह उससे कहीं कम होगा। जितना मर्ज़ी पैसा खर्च हो गया हो, आप वह हमें मत दिखाइए। एस्टिमेट्स मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य ज़िन्दगियाँ जा रही हैं, खत्म हो रही हैं। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव के कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए। धारी देवी को पुनर्स्थापित करिये। उत्तराखंड को अगर बचाना है तो राहत और पुनर्वास तो अलग है, लेकिन जब तक धारी देवी का पुनर्वासन नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी राहत और पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो सकेगा।

सभापति जी, जहाँ तक पुनर्वासन और राहत के कार्य का सवाल है, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे भाई सैयद शाहनवाज़ हुसैन यहाँ से मैम्बर थे, भगत सिंह कोष्यारी जी सांसद वहाँ से मैम्बर थे और उमा भारती जी नेतृत्व कर रही थीं। वे तीनों वहाँ गए थे। एक एक जगह जाकर वे देखकर आए। जो रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी, वह बहुत आश्चर्यजनक थी। मैं राहत और पुनर्वासन के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर रही हूँ - एक तात्कालिक कार्य और दूसरा दीर्घकालिक कार्य। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि आप चौंक जाएँगे कि क्या आपने वहाँ दिया है और क्या वहाँ पहुँचा है। सभापति जी, वहाँ की सरकार ने गाँवों को विस्थापित करके पुनर्वासन करने के लिए 8000 करोड़ रुपये और रीकंस्ट्रक्शन के लिए 5000 करोड़ रुपये, इस प्रकार 13 हज़ार करोड़ रुपये मांगे हैं। केन्द्र सरकार ने उसके विरुद्ध 1000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। उस 1000 करोड़ रुपये के विरुद्ध आपने 250 करोड़ रुपये रिलीज़ किये हैं और वे 250 करोड़ रुपये पुरानी आपदा जो आई थी, उसके बकाया थे। वे 250 करोड़ रुपये उसमें एडजस्ट हो गए हैं और ज़ीरो पैसा बचा है आपदा कार्य के लिए। एक पैसा आज उनके पास आपदा राहत कार्य के लिए नहीं है। इसी तरह से बॉर्डर रोड्ज़ आर्गनाइज़ेशन को आपने 300 करोड़ रुपये रिलीज़ किये थे। 270 करोड़ रुपये उनके पिछले बकाया थे। वे एडजस्ट करने के बाद मात्र 30 करोड़ रुपये बचे हैं। 30 करोड़ रुपये में आप कौन सी सड़कें बना देंगे?

तीसरा, खच्चर के लिए 10 हज़ार रुपये केन्द्र सरकार ने और 15 हज़ार रुपये राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। खच्चर 70-80 हज़ार रुपये से कम में नहीं आता है। आपके 15 हज़ार रुपये लेकर वे क्या करेंगे? एक आदमी भी एक खच्चर वहाँ से खरीद नहीं सकेगा। चौथा, वहाँ का पर्यटन पूरी तरह से समाप्त हो गया है और पर्यटन समाप्ति में वहाँ के मुख्य मंत्री के बयान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं कि वहाँ के मुख्य मंत्री ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की ओर मुँह मत करना। और अगर कोई आए तो अपनी ज़िम्मेदारी पर आए, हम उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसा बयान मुख्य मंत्री देते हैं। आप जानते हैं कि आज भी उत्तराखंड में मसूरी, धनौल्टी, औली, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, रामगढ़, हरिद्वार और नैनीताल, ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन पर आपदा का कोई असर नहीं है। इसलिए अगर पर्यटकों को वहाँ आने दिया जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था बहाल हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्य मंत्री, मैंने कहा ना कि वैसे ही सुस्त मार्का हैं, वे तो चाहते ही नहीं हैं कि कोई आए। वे कह रहे हैं कि कोई मुँह मत करना उत्तराखंड की तरफ। वहाँ का पर्यटन पूरी तरह समाप्त हो गया है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आज भी बद्रीनाथ में 1000 वाहन फँसे हुए हैं जिसके विरुद्ध उन्होंने ऋण लिया हुआ है। उनके लिए रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हुआ है। उस ऋण की माफ़ी के लिए भी मैं आज आपसे अनुरोध करती हूँ कि उस ऋण को भी आप माफ करें। होटल, दुकानें खोलने के लिए बैंकों से लोगों ने ऋण ले रखे हैं। उन ऋण की माफी के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करती हूं। सबसे अधिक किल्लत गैस की है। होटल और दुकानें बंद हो गए हैं। केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे तो हम देंगे। मैंने कहा न कि राज्य सरकार तो ऐसे ही सुस्त मार्का है। वह प्रस्ताव ही नहीं भेज रही है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी नहीं, आप गैस देंगे नहीं तो किस तरह से वह होटल और दुकानें खुलेंगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव की अपेक्षा मत कीजिए, राज्य सरकार को तो बर्खास्त कर दीजिए, अपने नीचे ले लीजिए उत्तराखण्ड को।

सभापति जी, आपदा पीड़ितों की राशि के नाम पर एक रुपया भी किसी को नहीं मिला है। यह जितने नाम मैंने अपने यहां के बताए हैं, रायसेन जिले के दस, विदिशा के 23, नसुल्लागंज के 23, उनको मध्य प्रदेश सरकार ने दो-दो लाख रुपये अपनी तरफ से दिया है। आपने कहा है कि साढ़े तीन-तीन लाख रुपये आप देंगे। उत्तराखण्ड सरकार ने कहा था कि साढ़े तीन वह देंगे। इस तरह से सात-सात लाख रुपये उन्हें मिलने थे। अब उत्तराखण्ड ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार दे और राज्य सरकारें जितना देना है दें।...(व्यवधान)

SHRI S. SEMMALAI(SALEM) : Madam, Tamil Nadu Government has given Rs.5 crore.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : That you will speak.

राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी ओर से जो देना था, वह दिया है। हमारे यहां दो-दो लाख रुपये उन्होंने दे दिए। अगर उत्तराखण्ड सरकार और नहीं देगी तो बकाया भी हम दे देंगे। लेकिन आप साढ़े तीन-तीन लाख रुपये जो देने वाले हैं, साढ़े तीन कौड़ी भी नहीं दिया है आपने अभी तक, साढ़े तीन कौड़ी। मैंने आपसे कहा न कि आपके पास आंकड़ा ही नहीं है तो आप देंगे कहां से? पहले आप आंकड़ा जुटा लीजिए और यह पैसा देना शुरू कीजिए। वह लोग कहां तक इंतज़ार करेंगे? एक पैसा भी आपदा राहत राशि के नाम पर अभी तक आपने नहीं दिया है।

एक और बात सभापति जी, मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि ढाबा, खोमचे और चाय की दुकानों का मुआवजा, एनडीआरएफ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर यह दुकानें खत्म हो जाती हैं तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री जी इन मानकों को बदलवाइए। वहां लोगों ने ढाबे खोल रखे थे, खोमचे थे, चाय की दुकानें थीं, अगर यह मानक नहीं बदले जाएंगे तो एक रुपया भी उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए इन मानकों को भी बदलवाइए।

दसवीं बात, 256 गांव आज भी वहां सड़क मार्ग से वंचित हैं। इसलिए न खाद्यान्न पहुंच पा रहा है, न मेडिकल एड पहुंच पा रही है, न पेयजल पहुंच पा रहा है। इन 256 गांवों की, जिनकी कनैक्टिविटी खत्म हो चुकी है, वहां जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग बनवाकर के उनके साथ कनैक्टिविटी जोड़िए ताकि उनको खाद्यान्न और पेयजल दिया जा सके।

इसके साथ मैं कुछ दीर्घकालिक उपायों की बात कर रही थी। गृह मंत्री जी पन्ने मत पलटिए, मेरी बात सुन लीजिए।

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): मैं सुन रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिए। इसको बंद कर दीजिए, मेरी बात सुनिए।

मैं इसलिए कह रही हूं ताकि दोबारा आपदा न आए। दीर्घकालिक उपाय इसलिए हैं कि ऐसी आपदा दोबारा न आए और उसके लिए हम को क्या करना चाहिए? एक तो पूरे उत्तराखण्ड की जीआईएस मैपिंग करवाइए। जीआईएस मैपिंग से आपको यह पता चल जाएगा कि कहां सड़क है, कहां हेलीपैड है, कहां होस्पीटल है, कहां स्कूल है और यह जीआईएस मैपिंग की सीडी बनवा लीजिए, जो हर अधिकारी के पास होनी चाहिए ताकि कल को खुदा-न-खास्ता अगर दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उनको ढूंढेर न मचानी पड़े। क्योंकि जो अधिकारी वहां आए थे, जो उस समय भी लगे थे, वह कोई उत्तराखण्डी नहीं थे। ज्यादातर लोग दक्षिण महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए लोग थे। उन लोगों को पता भी नहीं था क्योंकि वह तीन-तीन महीने पहले ही वहां लगे थे। उन्हें जगह के बारे में भी मालूम नहीं था। अगर उनके पास जीआईएस मैपिंग की सीडी होगी तो केवल उसी से वह यह अंदाज लगा लेंगे कि कहां स्कूल है, कहां सड़क है, कहां हेलीपैड है। इसलिए आप जीआईएस मैपिंग करवाइए। दूसरा, जब यात्रा शुरू हो तो हर यात्री का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए। उसको एक माइक्रो चिप दीजिए ताकि उसकी लोकेशन का पता लग सके। अगर आपको ढूंढ़ना हो तो माइक्रो चिप से यह पता लग जाए कि उसकी लोकेशन क्या है। तीसरा, आप वहां के सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनवा दीजिए। पता नहीं आपदा कहां आती है, कहां से जाना पड़ता है? यह लोग उसी समय हेलीपैड बनाते हैं। यह जो कच्चा हेलीपैड बना था, उससे ही पहला हेलीकॉप्टर गिरा था। यह जो क्रैश हुआ, जिसमें बीस लोग मरे, उससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर गिरा था, क्योंकि हेलीपैड कच्चा था। इसलिए सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनावा दीजिए। चौथा, हर जिला अधिकारी के पास सैटेलाइट फोन होना चाहिए। आपने लिखा है कि सैटेलाइट फोन्स दिए। कब दिए? आपदा के बाद आपने सिंगापुर और हांगकांग से मंगवाए। मैं यही आप से कह रही हूं कि यात्रा की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। क्या सैटेलाइट फोन्स इस तरह की यात्रा में उत्तराखण्ड में नहीं होनी चाहिए थीं? आप ने ऑर्डर दिया, मंगवाए और मंगवाने के बाद दिए। सैटेलाइट फोन्स वहां उपलब्ध रहने चाहिए। आप वहां सैटेलाइट फोन दीजिए।

वहां ऑल-वेदर रोड्स बनाइए। वहां से चीन की सीमा 25 किमी0 पर लगती है। वहां ऑल-वेदर रोड्स हैं। अब यह कोई ऐसी तकनीक तो है नहीं कि चीन को मिल सकती है और हमें नहीं मिल सकती है। आखिरकार, इतनी बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया। उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी नॉन-कनेक्टिविटी। हम वहां जा नहीं पा रहे थे, हम केवल एयर-ड्रॉपिंग कर पा रहे थे। वह भी क्योंकि मौसम खराब था तो हेलिकॉप्टर जा नहीं पा रहा था। ऑल-वेदर रोड्स अगर चीन ने बनायी है तो आप वह तकनीक जापान से लीजिए, चीन से लीजिए। लेकिन वह टेक्नॉलोजी ले कर ऑल-वेदर रोड्स बनाइए। अगर ऑल-वेदर रोड्स बने होंगे, सब गांवों में हेलिपैड्स होंगे, जिलाधिकारियों के पास सैटेलाइट फोन्स होंगे, उनके पास जी.आई.एस. मैपिंग होगी और यात्रियों के पास माइक्रो चिप होगी तो यदि कभी भी इस तरह की चीज़ सामने आ जाए तो उसका हम कहीं ज्यादा दुरूस्तगी के साथ सामना कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने दीर्घगामी उपाय आप को कहा है, ये सारे उपाय आप नोट कर लीजिए और ये उपाय करिए।

मैं आप से फिर कह रही हूं कि आप की सरकार ने न तो यात्रा की पूर्व-तैयारी की, न यात्रियों को एलर्ट किया, न यात्रा के दौरान संवेदनशीलता दिखायी। क्या आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने कहा था कि हम दो-दो हजार रुपये हर यात्री को देंगे? राजस्थान की एक महिला का इंटरव्यू मैंने देखा। उस ने कहा कि अधिकारी यहां बैठे हैं। वे दो हजार रुपये की जगह दो सौ रुपये या पांच सौ रुपये दे कर हम लोगों से दो हजार रुपये के ऊपर साईन करवा रहे हैं। यह मैंने जो कहा वह राज्य सरकार की अकर्मण्यता और लुटेरों की संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा थी, वह इन्हीं चीज़ों के कारण कहा था। अगर शवों की उंगलियां काट कर अंगूठियां निकाली जाएंगी, अगर मृतक देहों से गहने उतारे जाएंगे, शवों को अधजला छोड़ा जाएगा तो जिन पराकाष्ठाओं की बात मैंने की है, उन पराकाष्ठाओं को अपने तथ्यों से पुष्ट करने का भी मैंने काम किया है और सुझाव देने का काम भी किया है।

महोदय, मैं चाहूंगी कि अगर इस चर्चा को आप ने सार्थक बनाना है तो इन तमाम चीज़ों को दर्ज़ करिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मैंने कहा है कि गंगा जी के ऊपर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए। मैं धारी देवी के सामने प्रार्थना करते हुए कहती हूं कि मैया, ऐसी आपदा कभी उत्तराखण्ड में क्या पूरे देश में कहीं किसी को न झेलनी पड़े। यह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और धारी देवी को पुनर्स्थापित कर दें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, आप ने उत्तराखण्ड की आपदा के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरा देश रो रहा है, गढ़वाल रो रहा है, कुमायूं रो रहा है, उत्तराखण्ड रो रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को कुछ पौराणिक काल की बातें याद दिलाना चाहता हूं। पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि परमात्मा ने मनु महाराज से कहा कि मैं धरती को जलमग्न कर दूंगा। विश्वात्मा प्रभु ने मत्स्य रूप धारण किया और मछली बना कर ऋषियों का उद्धार किया और पृथ्वी जलमग्न हो गयी। इसी प्रकार से नोहा के बारे में आता है कि याहुआ ने नोहा से कहा कि मैं पृथ्वी को पानी से ढंक दूंगा, तुम एक नौका बनाओ और उसमें जीव-जन्तु के एक-एक जोड़े को रखो। इसी प्रकार से, हज़रत नूह को भी अल्ला तालाह ने फरमाया और कहा कि मैं धरती को पानी से ढंक दूंगा। यह पानी पृथ्वी को ढक देता है। आखिर यह किस चीज़ का परिणाम है? अगर इसको हम साइंटिफिकैली देखें, this is nothing but Global Warming. यह जो प्रकृति के अन्दर गर्मी पैदा हो रही है, इससे हमारे हिम शिखर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पहाड़ों के अन्दर जो हमारे गोमुख हैं, जहां से हमारी नदियां प्रारंभ होती हैं, वहां बाढ़ आ रही है। यह केवल मातृ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है।

महोदय, मैं आपके सामने "दैनिक जागरण" में छपे एक लेख का उल्लेख करना चाहूंगा। यह दैनिक जागरण 2 अगस्त, 2004 का है। लक्ष्मी प्रसाद पंत देहरादून से

लिखते हैं - आस्था के सर्वोच्च शिखर से केदारनाथ धाम पर कभी भी चौराबाड़ी ग्लेशियर बम की तरह फट कर कहर बरपा सकता है। मंदिर के ठीक पीछे स्थित छः किलोमीटर लम्बे इस ग्लेशियर से हिमस्खलन लगातार सक्रिय हो रहे हैं, जब कि मौसम के गर्म होने से चौराबाड़ी के इर्द-गिर्द बर्फीली झील की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, चूंकि ये झीलें ग्लेशियर की पीठ के ऊपर सवार हैं, इसलिए अगर पानी का बोझा बढ़ा तो झीलें फट पड़ेंगी और मौका ताड़ कर यमनोत्री और बद्रीनाथ से भीषण तबाही केदारनाथ धाम में मचाने निकल पड़ेगी। चौराबाड़ी ग्लेशियर का सर्वेक्षण पूरा कर हाल ही में केदारनाथ से लौटे नामचीन हिम विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर अगर आप गौर करें तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे विशेषज्ञों ने 2004 में ही इस बात का उल्लेख कर दिया था। ये उल्लेख यह दर्शाता है कि अगर पानी बरसा, बारिश का जो पानी होता है, वह गर्म होता है और वह गर्म पानी अगर ग्लेशियर पर पड़ता है तो ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं और अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है। ये बात मैंने कही। अभी विपक्ष की नेता जी ने उल्लेख किया, धारी देवी का उल्लेख किया। धारी देवी कोई शिला नहीं है। धारी देवी एक मूर्ति है, जो कालीमठ से पानी में बहते-बहते वहां आई। किसी व्यक्ति को स्वप्न में भगवती ने कहा, मुझे यहां से निकालो, वह मूर्ति निकाली गई और वह शिला के ऊपर रख दी गई। उस धारी देवी का कोई छत्त वाला मंदिर नहीं है, वह केवल आसमान के नीचे रहती है। वह पानी में बहते-बहते वहां पहुंची। जो उल्लेख किया गया कि धारी देवी को ऊपर उठा दिया गया, जिसके कारण यह बताया जाता है कि बाढ़ आई। मैं यह कहना चाहूंगा कि केदारनाथ के अंदर जो आपदा आई, वह 16 तारीख को छः बजे सुबह आई। चौराबारी के ग्लेशियर फटे, वर्षा बहुत हो रही थी, वर्षा का पानी गर्म था। गर्म पानी जब ग्लेशियर पर गिरा तो बहुत तेजी से बर्फ पिघलने लगी। पानी की क्वांटिटी बढ़ गई, नदी चौगनी हो गई और चार गुना वोल्यूम से जब बहने लगी तो निश्चित रूप में 16 तारीख को छः बजे सवेरे हल्की सी बाढ़ आई। भगवती धारी देवी का वहां से जो स्थानांतरण किया गया, वह 16 तारीख को शाम को साढ़े छः बजे किया गया। दूसरी बात वह आती है, जिसमें हमारे काफी ग्लेशियर फटे, चौराबारी का ग्लेशियर फटा तथा अन्य भी फटे। वह 17 तारीख को आती है और 17 तारीख के अंदर उसने नरसंहार मचा दिया। हमारी नदियां इतनी बहने लगीं कि अगल-बगल में जो बीआरओ की सड़क थी, नेशनल हाईवेज़ थे, वे बह गए और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक तांडव हो गया। उत्तराखंड के पांच जिले आपदा से विकट रूप से प्रभावित हुए हैं। रूद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, कालीमठ, जाल चौमासी, बक्सीर बांगर, रासी, गोंडार तथा चमोली जिले में गोविन्दघाट, पांडुकेश्वर, थराली, घाट, नारायणबगड़, उर्गम, लोहाजंग, उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी, गंगोरी, भटवारी, हर्षिल और पिथौरागढ़ जिले में धारचूला, जौलजीबी, मदकोट, बालुवाकोट, तवाघाट और बागेश्वर जिले में कपकोट आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर गांव बड़े बुरी तरीके से प्रभावित हुए। पानी ऊपर से बहता रहा, लोगों को मकान छोड़ने पड़े। रामबाड़ा पूरे तरीके से बह गया। आज नक्शे में रामबाड़ा नाम की आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। गांव धंसने लगे। इस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में 17 सौ गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और चार हजार गांवों पर गंभीर रूप से आपदा का प्रभाव पड़ा है। आपदा में दूसरे राज्यों से लगभग 4481 लोग लापता हैं, उत्तराखंड राज्य के 800 लोग लापता हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 1898 भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें रूद्रप्रयाग जिले के 430 तथा चमोली जिले के 355 भवन सम्मिलित हैं। जब आपदा की सूचना लेकर हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोनिया जी का वैसे भी प्रेम चमोली से रहा है। जब-जब वहां भूकम्प आया, जब-जब चमोली में आपदा आयी, सोनिया गांधी वहां देखने के लिए पहुंचीं। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि जो भी मदद होगी, हम पूरी-पूरी उत्तराखण्ड की मदद करेंगे और नवनिर्माण के लिए पूरे तरीके से सहायता करेंगे।

महोदय, हम लोगों ने यह मांग की कि बॉर्डर रोड्स अपना काम चालू करे। जगह-जगह जो सड़क टूट गयी है, उसका रीएलाइनमेंट होना चाहिए। रीएलाइनमेंट से आप सड़क को ऊपर ले जायेंगे। बॉर्डर रोड्स केन्द्र सरकार के अधीन है, बल्कि उत्तराखण्ड के अन्दर जो पीडब्ल्यूडी है, वह भी अपनी सड़कों को और बाईलेन्स को, जो छोटी-छोटी सड़कें हैं, उनको चालू करे।

चमोली जिले के गोविन्दघाट में फंसे हुए दो हजार खच्चर निकाले गये। मैं यह बताना चाहूंगा कि खच्चरों को जब भोजन नहीं मिला, घास नहीं मिली तो खच्चर रेत खाने लगे। यहां तक कि खच्चर आदमियों पर झपटते थे, आदमियों को खाने को दौड़ते थे। उन खच्चरों को बड़ी मुश्किल के साथ निकाला गया। केदारनाथ क्षेत्र में फंसे हुए खच्चरों को निकाला गया और चारा भी उनको दिया गया। उर्गम, गोविन्दघाट, भ्यूंडार, पुलना, सुनाली, जेटी, नोली-हिण्डोली-बांतुली, जस्यारा, नौसारी, बड़सूली, पिंडर व लोहाणी घाट में बादल फटने से भी और भीषण आपदा आयी। उत्तराखण्ड आपदा में रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के 90 मोटर व पैदल पुल मार्ग बह गये, जिनमें 20 महत्वपूर्ण पुल थे। चौथानी, नालाई, मुलुण्ड, मलगांव, बागवान, भूरागाड़, हरमल, सकुलीगाड, चौप्पडियां, कालीमठ, चन्द्रपुरी, सिल्ली, मल्यासू तथा धारचूला में काली नदी का पुल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि इस राज्य में 1,956 सड़कें बंद हो गयीं, 968 पेय जल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गयीं, 135 पुल क्षतिग्रस्त हो गये। इसी प्रकार से बहुत जगह विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी और दूरसंचार सेवाएं ठप्प हो गयीं। मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने तत्काल एक हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, पर्यटन मंत्री जी को, जिन्होंने तत्काल 100 करोड़ की सहायता प्रदान की, विभिन्न मंत्रालयों एवं उनके अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों ने लगभग 840 करोड़ की सहायता प्रदान की। रेल मंत्रालय ने आपदा में फंसे हुए दूसरे राज्य के निवासियों को नःशुल्क उनके घर तक पहुंचाया तथा प्रभावितों के लिए राहत सामग्री विभिन्न राज्यों से नःशुल्क पहुंचायी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले बीस हजार सोलर लाइटें बांटी, अब फिर वे बीस हजार लाइटें और बांटने को तैयार हैं, ताकि उत्तराखंड के जो घर हैं, उनके अंदर अंधेरा न रहे। डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा आपदा में ध्वस्त हुए मकानों के पुनर्निमाण के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा राजीव गांधी आवास योजना द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि वे मकानों का पुनर्निमाण करायेंगे। श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा नष्ट हुए आंगनबाड़ी भवनों का पुनर्निमाण का संकल्प लिया गया है। एयरफोर्स द्वारा सी-130 जे एयरक्राफ्ट, साथ ही 45 हैलीकाप्टर्स लगाकर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया, सेना द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, साथ ही साथ आईटीबीपी, एसएसबी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा स्थानीय युवकों ने लोगों को बचाने में बहुत-बहुत मदद की।

सांसदों ने अपना वेतन और एमपीलैड से हम लोगों को सहायता पहुंचायी। मैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देश की जनता, संस्थायें, कारपोरेट्स, संतों, सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 6,600 करोड़ रूपए के पैकेज की स्वीकृति दी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतनी सहायता देने के बाद और जो सेना ने कमाल किया, हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने, आईटीबीपी, एसएसबी ने लोगों को बचाया, उनके लिए मैं सलाम करते हुए यह कहना चाहूंगा कि कमाल तुम हो, कमाल हम भी कर देंगे, वफा की कायम मिसाल कर देंगे, हम एहले मेला तुम्हें दोस्ती के तोहफे में, चमन के फूल नहीं दिल निकालकर रख देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं सिर्फ दुआ के सिवा, दुआ देकर ही हम तुम्हें मालामाल कर देंगे।

मैं सभी लोगों को जिन्होंने बहुत-बहुत मदद की है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि भारतीय वायु सेना ने 45 हैलीकाप्टर से 23,775 लोगों को बचाया। उन्होंने लगभग 3,470 सोर्टिज भरी, उड़ानें भरीं। भारतीय सेना ने आठ हजार कर्मियों, 150 बलों और 12 हेलीकॉप्टरों की तैनाती से 38,750

व्यक्तियों को बचाया। इस बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के नौ कर्मियों तथा आई.टी.बी.पी. के छः कर्मियों सहित वायुसेना के पांच कर्मियों की एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, मैं उनको अपनी तरफ से तथा सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, परकोट और हरसिल में तत्काल संपर्क प्रणाली स्थापित करने के लिए सौ से अधिक सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गये। भारत सरकार ने अपेक्षित उपकरणों सहित 80 चिकित्सक, 11 मनोचिकित्सक तथा पांच लोक स्वास्थ टीमें भेजकर सहयोग दिया। विभिन्न जिलों के लिए एस.टी.आर.एफ. सी.एम. रिलीफ फंड तथा टी.आर.-24 से जिलाधिकारियों को कुल 28 करोड़ 99 लाख 17 हजार की राशि दी गयी। जिसके सापेक्ष 18 करोड़ 80 लाख 22 हजार की राशि व्यय की गयी। राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 1,998 भवन क्षतिग्रस्त हैं। जिनमें रुद्रप्रयाग जिले के 430 तथा चमौली जिले के 355 भवन सम्मिलित हैं। प्रदेश के लगभग 375 परिवार धर्मशालाओं में तथा 780 परिवार 2000 रु. महीना के किराये पर रह रहे हैं। आपदाग्रस्त गांवों की संख्या करीब एक हजार है। जिसमें अब भी हमें 344 गांवों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से और पैदल मार्ग तथा खच्चरों के मार्ग से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय एक समस्या पैदा हो गयी है। जो लोग लापता हैं, उनको परज्यूम्ड डेड माना जाए। आर्मी के अंदर जब लाश नहीं मिलती है, तो यह माना जाता है, एक टेक्निकल वर्ड है, परज्यूम्ड डेड। तो उनको परज्यूम्ड डेड मानकर आर्थिक सहायता दी जाए और सहायता देने के बाद उनके बच्चों को कमपैसनेट ग्राउंड पर नौकरी मिल सके। उनके पेंशन फंड्स, उनकी तनख्वाह उनको पूरी तरह से मिल सके, तो यह परज्यूम्ड डेड बहुत ही जरूरी है।

मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनामी की तर्ज़ पर, क्योंकि सुनामी में भी लाशें नहीं मिली थीं, तो सुनामी की तर्ज़ पर वे निश्चित रूप से इसे देखेंगे और जो लोग इस समय लापता हैं, उन्हें परज्यूम्ड डेड मान लिया जाएगा। बी.आर.ओ. और पी.डब्ल्यू.डी. तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण कराए और जो कर्मचारी तथा अधिकारी आपदा में दिन-रात काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाए, जिससे उनका मनोबल बढ़े। हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर सेवा की है उनकी पीठ निश्चित रूप से ठोकी जानी चाहिए। तो जिन कर्मचारियों ने रात और दिन पब्लिक को फेस किया, जनता की बहुत सी बातों को फेस किया, उनको निश्चित रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। जगह-जगह ट्रॉलिज लगनी चाहिए, ताकि एक पहाड़ की तरफ कोई महिला प्रेगनैंट है और प्रसव देने जा रही है तो उसको ट्राली के जरिए दूसरी जगह पहुंचाया जाए। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि इस आपदा की सही-सही फोरकास्टिंग कर सकें तो हमें उत्तराखंड के अंदर डॉप्लर राडार लगाने होंगे। इसका मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था और नैनीताल के अंदर डॉप्लर राडार लग गए हैं, परन्तु हमारे गढ़वाल क्षेत्र की तरफ डॉप्लर राडार्स नहीं लगे हैं। इससे हम लोग यह पता लगा लेंगे कि कहा पर बादल फट रहा है और कहां ज्यादा बारिश हो रही है और कहां पर खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड के अंदर डॉप्लर राडार का लगना बहुत जरूरी है। विस्थापन पुनर्वास के लिए जमीन जो है, लैंड मार्क होना चाहिए और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट आनी चाहिए कि यहां पर जो पुनर्निमाण होगा, वह सुरक्षित होगा, अब यह जमीन नहीं धसेंगी, इस प्रकार का एन.ओ.सी. प्राप्त होना चाहिए। बहुत-से लोगों ने संकल्प लिया है, बहुत से साधु-संतों और कारपोरेट्स ने कहा है कि हम आपके मकान बनाना चाहते हैं। हम उत्तराखंड के अंदर निर्माण करना चाहते हैं। उत्तराखंड हमारा वह प्रदेश है, जहां से गंगा बहती है, यह देवभूमि है, हम देवभूमि का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए जब उन्होंने संकल्प लिया है, उन के अंदर भावना नवनिर्माण करने की है, तो ऐसे समय में हमें जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट ले कर सुरक्षित स्थानों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोगों को नीचे बसाएंगे तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है, वहां कौन सुरक्षा करेगा।

सभापति महोदय, मेरा यह भी मानना है कि पहाड़ में नीति और माणा बार्डर एरिया चीन से मिलता है। वहां पर लोग बसें, ताकि हमारे देश की सुरक्षा हो। इसीलिए शंकराचार्य जी ने चार धामों की स्थापना की थी। बद्रिका आश्रम धाम की स्थापना इसीलिए की थी कि भारत के मस्तक की रक्षा हो। आज जब हम केदारनाथ और बद्रीनाथ का नाम लेते हैं तो सारे देश की भावना जुड़ जाती है। देश को एक रखने के लिए उन्होंने चार धामों को चार दिशाओं के अंदर स्थापित किया। इसीलिए हमारे आदि शंकराचार्य राष्ट्रवादी थे। आज उनके विचारों को लेते हुए हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार वहां प्री-फैब्रिकेटेड हाउसेज बना सकते हैं और पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही बसा सकते हैं, क्योंकि उनके देवी-देवता, उनका भूमिया जिसे हम भूमि देव कहते हैं, सब पहाड़ों में ही हैं। उनकी खेती पहाड़ों में ही है। इसलिए उन्हें पहाड़ों में बसाने का काम करना चाहिए।

यहां टूरिज्म की बात कही गई। हम टूरिज़्म में बहुत पिछड़ गए हैं। आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर बार-बार एक चित्र आता था कि शिवजी की मूर्ति बाढ़ के पानी में बह रही है। लोगों ने समझा कि ऋषिकेश और हरिद्वार पानी में डूब गया है। इस प्रकार बहुत नेगेटिव प्रचार हो गया। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और रामनगर सुरक्षित है। निश्चित रूप में मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा कि वे हमारे उत्तराखंड में आएं और देव भूमि का दर्शन करें। वहां हमें धामों का विस्तार करना होगा। आज चार धाम हैं - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। परन्तु वहां जो भगवती के अनेक स्थल हैं, हमें उन्हें भी डैवलप करना होगा। चंद्रवदनी को डैवलप करना होगा, ज्वाल्पा को डैवलप करना होगा। वहां कार्तिकेय स्वामी को डैवलप करना होगा। जो और धाम हैं, अगर उन्हें विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से यात्री उत्तराखंड की तरफ आएंगे। उत्तराखंड में ऐसे स्थान हैं जहां फुनिकुलर रेलवे लग सकता है। ग्रीस के अंदर फुनिकुलर रेलवे से लोग चलते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी फुनिकुलर रेलवे लगना चाहिए, रोपवे लगने चाहिए।

मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि 11 सितम्बर को केदारनाथ, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहां पूजा प्रारंभ होने जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है क्योंकि आप जानते हैं कि जब पांडव आए, पांडवों ने जब अपने स्वजनों की हत्या कर दी तो वे कृष्ण के पास गए। कृष्ण से कहा, महाराज हमारा कैसे उद्धार होगा। कृष्ण ने कहा, तुम जाओ, शंकर जी के दर्शन करो। शिव के दर्शन करोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। जब वे शिव के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे तो केदारनाथ में शंकर जी ने अपना सिर जमीन में डाल दिया। यह माना जाता है कि वह सिर नेपाल में निकला। वही शिव नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से हैं, भारत में केदारनाथ के नाम से हैं। वही शिव हैं, एक आत्मा है पर दो देश हैं। इन दोनों देशों को जोड़ने वाली शिव की वह शक्ति है जिसका पूजन 11 तारीख को होगा। मैं इसके लिए भी लोगों को आमंत्रित करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में त्रासदी आई है।

अभी बहुत सी जल विद्युत योजनाओं के बारे में कहा गया कि हम जगह-जगह बांध बना रहे हैं। वैसे टेहरी बांध बनने के बाद पहाड़ों में अब बांध नहीं बन रहे हैं। केवल यह कि रन ऑफ दी रिवर से पानी ले जाकर आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। देश को ऊर्जा चाहिए। सेफ ऊर्जा जल विद्युत योजना है। आपने देखा होगा कि जापान में फ्यूकोशिमा हुआ। चेरनोबल में न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ। यहां तक कि आज तक गायगर काउंटर से देखा जाता है कि जो मक्खन आ रहा है, दूध आ रहा है, उसमें रेडियोएक्टिव प्रभाव तो नहीं है। आपने देखा होगा कि जापान से जो टोएटा कारें लाई गई हैं, उन्हें रीकॉल किया गया था क्योंकि समुद्र का रेडियोएक्टिव पानी उनके अंदर घुस गया था। इस प्रकार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो विकल्प है, वह हमारी जल विद्युत योजना है। गंगा मां बह रही है। गंगा मां का मतलब होता है कि मां जो सबका पोषण करे, पालन करे। अगर गंगा बिजली बना रही है और देश के नवनिर्माण, भारत निर्माण में अपना सहयोग दे रही है, तो हमें बड़े सुरक्षित रूप से वैज्ञानिकों की सलाह लेकर, पर्यावरणविदों की सलाह लेकर यह काम करना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। इसके साथ-साथ सोलर एनर्जी का उत्तराखंड में प्रचार करना है। विंड एनर्जी का प्रचार करना है। हमारे पहाड़ों में बहुत हवा बहती है। उससे हम विंड टरबाइन

लगाकर, पवन चक्कियां लगाकर बहुत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। हमारा यही एक विचार है, यही संकल्प है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाएं। इसीलिए हमने उसे ऊर्जा प्रदेश कहा था क्योंकि हमारे अंदर बहुत पोटैंशियल है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जल विद्युत योजनाएं केवल मात्र यह देखकर कि बहुत बड़ी आपदा आ गई, बंद न की जाएं, उन पर विचार-विमर्श हो। आप सब लोगों का उसमें सहयोग हो और विचार-विमर्श के बाद यह तय किया जाये कि अपने देश के निर्माण में कैसे उत्तराखंड का योगदान होगा। इन सब चीजों को सोचकर हमें निर्णय लेना होगा।

सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि --

जब एक कड़ी से बावस्ता एक और कड़ी हो जाती है,

तो रस्में-मोहब्बत में फंसकर जंजीर बड़ी हो जाती है।

हम तो क्या हैं दोस्त, एक इंसा हैं,

पत्थर भी अगर मिल जाते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है।

आइए, इस सदन से हम यह संकल्प लें कि उत्तराखंड का निर्माण करेंगे, अपनी देव-भूमि का निर्माण करेंगे। जैसे आपने अपना एमपीलैड देकर हमें सहयोग दिया, उसी प्रकार से हम सब मिलकर, संकल्प लेकर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का निर्माण होगा और जो लोग आज आसमान के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं, उनको मकान मिलेंगे, छतें मिलेंगी और रोजगार मिलेगा। इन सबका संकल्प होना चाहिए। हम सबका योगदान होना चाहिए और इसी भावना से कि--

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः,

सर्वे भद्रानि पश्यन्ति मा कश्चिद् दुख भागभवेत।

MR. CHAIRMAN: Let us continue this discussion tomorrow.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I would request the hon. Minister to reply tomorrow to this discussion on Uttarakhand.

Now the RTI Bill may be taken up. ...(*Interruptions*)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोर्टैंट इश्यू है। ...(व्यवधान) हम दस दिन तक उत्तराखंड में थे। ...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी: इस पर कल चर्चा होगी। ...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : ऐसा कैसे हो सकता है। ...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Tomorrow I will be continued. आप सेंस ऑफ दी हाउस को देखिये। आप क्यों शोर कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : शोर नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : आप इस पर कल चर्चा कर लीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, let the Minister speak first.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप क्या बोल रहे हैं? आप उन्हें बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

18.58 hrs. (Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

DR. M. THAMBIDURAI : It was decided that the issue of Uttarakhand would be taken up today and other Bills would be taken up tomorrow. ...(*Interruptions*) Members have left on this assumption. You have not informed clearly at that time. Therefore, you see that discussion on Uttarakhand is taken up. ...(*Interruptions*) This is the consensus arrived at that time. You cannot change it now. ...(*Interruptions*)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। हम भी बोलना चाहते थे, लेकिन इस मामले में मैं तम्बिदुरई से कहूंगा कि ऊपर प्रैस गैलरी खाली है। यदि सदन में ही बोलना है, तो बोलिए। यदि कल बोलेंगे ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : We will take up Utharakhand tomorrow. There is no problem, we will continue tomorrow.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Now we shall take up the discussion under rule 193 regarding the natural disaster in Uttarakhand.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Mr. Chairman, Sir, it was decided that we will take up the RTI Amendment Bill and pass it today. If we do not complete it today, we will have to extend the Session.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उत्तराखण्ड पर चर्चा कम्पलीट करा दीजिए, जवाब कल दे दीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: We will have to sit late tomorrow.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। ...(व्यवधान) आज उत्तराखण्ड पर खुलकर चर्चा होने दीजिए। इस पर सब लोग बोलना चाहते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी है, इस पर चर्चा होने दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 193 के अधीन चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना और इधर से मंत्री जी के अलावा आपके विचार भी सुने। लेकिन उत्तराखण्ड पर जो बहस हो रही थी, यह बहस बहुत पहले होनी चाहिए थी। जब सत्र की शुरुआत हुई थी, उस समय यदि प्राथमिकता के आधार पर इसे लिया जाता, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। लेकिन देर से आए, पर दुरुस्त आए। जून के महीने में इतनी जबरदस्त बारिश हुई, जैसा कि अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 440 प्रतिशत ज्यादा वर्षा वहां पर हुई। वहां बादल फटने के अलावा जमीन हिली, भूकम्प आया, ग्लेशियर भी खिसके। ये प्राकृतिक आपदा के मुख्य कारण बने थे। आज हम यहां पर राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए चर्चा कर रहे हैं। जहां तक देखा गया है, अभी प्रतिपक्ष की नेता बहस कर रही थीं कि भारत सरकार ने किस प्रकार के उपाय किये और क्या कार्रवाई की।

रक्षामंत्री जी का भी जो वक्तव्य आया था, वह भी बहुत सही नहीं था। आपने अभी अपने वक्तव्य में सबको धन्यवाद दिया, लेकिन आज भी जब हम टेलीविजन देखते हैं, जिस समय हम लोग प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे थे, उसे टेलीविजन पर देख रहे थे, उस वक्त भी मैंने देखा कि समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर उत्तराखण्ड सरकार के विज्ञापन आ रहे थे। आप जानते हैं कि एक-एक विज्ञापन पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, तो जो पैसा लोग सांसद निधि से दे रहे थे, लोगों ने अपना वेतन दिया, बहुत से लोगों ने मदद की, उस पैसे का दुरूपयोग न हो, इसका ख्याल हमें रखना होगा। दूसरी बात, केन्द्र की जो आपदा प्रबंधन समितियां थीं, वे भी एक तरीके से सफेद हाथी साबित हुई। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जिले और राज्य के बंटवारे के बिल्कुल विरोधी रहे हैं और छोटे राज्य हमेशा दिक्कत, परेशानी और मुसीबतों का सामना करते देखे गए हैं। आज अगर उत्तराखण्ड बना, तो इस त्रासदी का मुख्य कारण यह था कि अपने पैर पर उत्तराखण्ड खड़ा नहीं हो सका था और इस प्रकार की दैवी आपदा आई है। आपदा में जो कंट्रोल रूम खोले गए थे, वहां पर भी सही जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही थी। यह गड़बड़ी थी। पूरे गांव के गांव तबाह हुए, आपने अपने वक्तव्य में कहा है। जहां तक वहां पहुंच पाने की बात है, अभी तक राहत कार्य के लिए लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और न ही राहत सामग्री पहुंची है। उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी कि लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एक हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिए थे, लेकिन 13 हजार करोड़ रुपये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी धनराशि है, इसलिए उसका सही मूल्यांकन करके उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण हो और उसमें केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए। जहां तक भारतीय वायु सेना और एयरक्राफ्ट्स की बात है, हमारे पायलट भी वहां मरे, एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ, थल सेना के हमारे जवानों ने बहुत मदद की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन, सशस्त्र सीमा बल, चिकित्सक सेवाओं एवं अन्य विभागों ने बहुत बेहतरी से वहां पर राहत पहुंचाई है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आज भी वहां की सरकार की ओर से 13 हजार 800 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने केवल एक हजार करोड़ रुपये दिए हैं, जो नाममात्र है।

महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ है, लेकिन उसके माध्यम से जो राहत पहुंचनी चाहिए थी, वह अभी तक नहीं पहुंच पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, हलफनामा मांगा है कि वहां पर आपदा राहत के रूप में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है। जहां तक लोगों के मरने की बात है, कितने लोग मरे हैं, आज भी एक संशय सा बना हुआ है। आज भी हम सही फिगर्स नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग लापता हैं। संशय यह बना है कि लापता लोगों को हम मृत घोषित करें या न करें या फिर वे लोग वापस आएंगे। यह आस लगाए हम इस तरह से ख्याली पुलाव नहीं बना सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग मरे हैं, हमें एग्जैक्ट संख्या बतानी होगी। जून से लेकर सितम्बर महीना आ गया, अब तक अगर किसी को वापस आना होता, तो वह व्यक्ति अपने घर वापस आ जाता, लेकिन अभी तक लापता और मरने वालों की संख्या ज्ञात नहीं है। ग्यारह हजार लोगों के मरने की बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने कही है, तो इसे भी हमें देखना होगा कि वह इनफार्मेशन सही है या नहीं। जहां तक मंत्री समूह की बात है, एंटनी साहब, पवार जी, चिदम्बरम जी और शिंदे साहब की टीम बनाई गयी है, मंत्रिमंडल के बड़े विद्वान सदस्यगण हैं, मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छी राहत का समन्वय होगा और राहत पहुंचाई जाएगी। आज भी वहां पर 245 सड़कें बंद हैं, 1500 करोड़ रुपये उन सड़कों की मरम्मत के लिए मांगे गए हैं, मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसको प्राथमिकता पर दे, ताकि राहत पहुंचाई जा सके। 752 गांव आज भी अलग-

थलग पड़े हैं, जहां पर राहत सामग्री और राहत कार्य नहीं पहुंच पाए हैं। किस राज्य से कितने लोग लापता हैं, मैं विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उनमें उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपये की राहत सामग्री और राहत के नाम पर नगद धनराशि के रूप में पहुंचाए हैं और तमाम ऐसे अन्य लोगों ने राहत पहुंचाई है, जिससे तमाम लोगों को इमदाद मिल सके।

जैसा आपने बताया कि आपदा क्षेत्रों में 31 मार्च, 2014 तक बिजली-पानी के बिल नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वहां पर क्या मुहैया करा पाए हैं, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की जहां तक बात है, बहुत पुराना मंदिर है और वहां सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। मैं चाहूंगा कि चाहे आईटीबीपी या इंडियन फोर्स या थल सेना के जो जवान शहीद हुए हैं राहत कार्य करते हुए, उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाए और उनके परिवार वालों को मदद दी जाए। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग वहां मर गए हैं या लापता हैं, उनके परिवार आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर मेरा कहना है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के जो दो लोग वहां मारे गए हैं, उनके आश्रितों को 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस तरह की घोषणा आपको भी करनी चाहिए, जिससे उनके परिवार वालों का जीवन स्तर उठ सके।

सभापति जी, मैं एक सुझाव और देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। जो पर्वतीय राज्य हैं, वहां के लिए केन्द्रीकृत नीति बनाई जाए। वहां पर ग्रीन बोनस लागू किया जाए और पहाड़ों के दोहन पर रोक लगाई जाए। जो अतिसंवेदनशील पहाड़ हैं, उन्हें इको सेंसेटिव जोन घोषित करके विकास का कार्य जो भी करना हो, बहुत सोच-समझकर किया जाए। यह भी देखा गया है कि पूरे उत्तराखण्ड में 13,000 लघु उद्योग या व्यावसायिक इकाइयां बर्बाद हो गई हैं। उनकी मदद करने की आवश्यकता है। इस आपदा के बाद जो गरीब हो गए हैं, जीवन गुरबत में गुजार रहे हैं, उसके कारण लड़कियों और बच्चों को अवैध व्यापार में झोंकने का काम किया जा रहा है। इसके लिए कई तत्व वहां पर सक्रिय हैं। सुनने में यह भी आया था कि जो लोग वहां मर गए थे, उनके कान, हाथ और गला आदि काट कर पहने हुए जेवरों को लूट लिया गया। इसे भी प्रदेश सरकार को देखना चाहिए।

इस आपदा के कारण वहां के खेतों को काफी नुकसान हुआ है और वे मलबे में दब गए हैं। उस जमीन को पुनः खेती लायक बनाने के लिए किसान भूमि सेना गठित की जाए या लोगों को अनुदान दिया जाए। उत्तराखण्ड में 45 बांध हैं। जो अवैध बांध हैं, जिनका निर्माण व्यापक रूप से हुआ है, तो नदियों को बांधने के कारण ही वहां इस प्रकार की दैवी आपदा आई है, क्योंकि इससे वहां की नदियों की धारा बदल जाती है। इसलिए पहाड़ों के साथ खिलवाड़ करने के कारण ही इस तरह की आपदा आई है। मैं चाहूंगा कि तमाम तीर्थ यात्रियों में उत्तराखण्ड का जो डर बना हुआ है, उसे दूर करने हेतु थोड़ी-बहुत यात्रा शुरू कराई जाए। इससे प्रदेश सरकार को भी राजस्व के रूप में कुछ मदद मिलेगी, जिससे राज्य सरकार अपने पैर पर खड़ी हो सकेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अपनी भाषण लिखित में देना चाहते हैं, वे सभा पटल पर अपना भाषण रख सकते हैं।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): सभापति जी, आपने मुझे अपने व अपनी बहुजन समाज पार्टी का विचार इस चर्चा में रखने हेतु मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखण्ड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण वहां रहने वाले ज्यादातर लोग बर्बाद, तबाह और उजड़ गए हैं। उनके पास सिर ढंकने के लिए न तो कोई अपना घर है और न ही रोजी-रोटी का कोई साधन बचे हैं। इस तरह से उत्तराखण्ड में बहुत बुरा हाल है। इस दैवी आपदा से उत्तराखण्ड में भारी बेरोजगारी बढ़ी है। यहां से आवागमन के समस्त साधन रोड, पुल इत्यादि सब टूट गए हैं। उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से आर्थिक स्रोत का साधन यहां के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल थे। लेकिन अब वहां का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से यह अपेक्षा रखता हूं कि उत्तराखण्ड में भारी तबाही से बर्बाद हुए उद्योगों, सड़कों, तीर्थ स्थानों व यहां के रहने वाले स्थानीय निवासियों के मकानों का पुनर्निर्माण उत्तराखण्ड में नए रूप में त्वरित गति से कराकर वहां के लोगों को बसाने में मदद करे।

इस क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सुझाव में कहा है कि न केवल उत्तराखण्ड, बल्कि देश में दूसरे जो पर्वतीय बाहुल्य राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहां केन्द्र सरकार को काफी ध्यान देने की जरूरत है। उन राज्यों के लिए केन्द्र सरकार को केन्द्रीय स्तर पर कुछ ठोस नियम और सख्त नीति बनानी चाहिए। ऐसे राज्यों में पहाड़ों के अंधाधुंध दोहन से रोकने के लिए ग्रीन बोनस और पहाड़ी इलाकों को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की तरफ आवश्यक कदम उठाना चाहिए। केन्द्र सरकार से मैं अपील करता हूं कि सरकार को उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावित परिवार के लोगों को फिर से बसाने के लिए, उनकी रोजी-रोटी के स्थायी प्रबंध आदि के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार को पूरी-पूरी हर संभव मदद करनी चाहिए।

उत्तराखंड त्रासदी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये जाने से घटी है। इस प्रकार जहां तक संभव हो सके पर्यावरण का और अधिक क्षरण न हो, इसके लिए भी ठोस व कारगर कदम उठाने की जरूरत है। इतना ही नहीं प्रायः देखने को मिलता है कि इन पहाड़ी इलाकों में बादलों के फटने से भी भारी धन और जन का नुकसान होता है, अर्थात इन हिल एरियाज में कभी भूस्खलन तो कभी बादल फटना और कभी इनसे भी बड़ी त्रासदी झेलने वाले यहां के लोग अपने आपको इसका आदी बना चुके हैं। उत्तराखंड में आयी इस कुदरती त्रासदी से लगभग 13 हजार से अधिक उद्योगों पर भी भारी तबाही आयी है। इन उद्योगों को पुनः पुनर्जीवित करने के लिए बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में सड़कों के किनारे आमतौर पर विकास हुआ है और सड़कें गंगा नदी व उसके अनुसंगीय नदियों के समानांतर बनायी गयी हैं। इस भीषण तबाही में नदी के किनारे बसे समस्त व्यवसायिक भवन, आवासीय भवन व सड़कें, बिजली के खम्भे, पारेषण लाइनें पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे छोटे-छोटे कारोबार, बिजली इकाइयां, होटल इत्यादि सभी बंद व बर्बाद हो चुके हैं। इन सब चीजों को बसाने के लिए उत्तराखंड को अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। अब तक केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दिया गया धन एक हजार करोड़ रुपये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि पुनर्वास हेतु उचित धन देकर उत्तराखंड वासियों को पुनः देश की मुख्य विकास की धारा से जोड़ने का काम करें।

MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to lay their written speeches on the subject can do so.

*__श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):__ हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में जिस तरह जल-प्रलय की विनाश लीला देखने को मिली उससे पूरा देश अचंभित एवं स्तब्ध रह गया । प्रकृति का यह रौद्र रूप चेतावनी देने के साथ-साथ हमें अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराने वाला है कि अगर चेता नहीं गया तो आगे भी देश

को ऐसी ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है । उत्तराखंड की इस विभीषिका के साथ-साथ हाल के वर्षों में सामने आई अन्य अनेक प्राकृतिक आपदाएं यह संकेत दे रही है कि खतरा लगातार गंभीर होता जा रहा है ।

आज प्रकृति की भीषण तबाही से त्रस्त उत्तराखंड वासियों के साथ भावनात्मक रूप से पूरा देश साथ खड़ा हे पर इसके साथ एक सवाल हमारे सामने है कि क्या शासन प्रशासन द्वारा उन गंभीर गलतियों को दूर करने के ठोस प्रयास किए जाएंगे जिनकी वजह से यह अभूतपूर्व तबाही हुई है । बांधों से हो रहे पर्यावरण विनाश को लेकर पर्यावरणविद बरसों से चेता रहे हैं लेकिन हमारी सरकारें बांधों को विकास का प्रतीक बताने का ढ़िढ़ोरा पीटते हुए उनकी नसीहतों को अनसुना करती रही है । देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तमाम तरह की बातें कही जाती हैं लेकिन धरातल पर शायद ही कुछ ठोस किया जाता है ।

आज यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि अति संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में जवाबदेह और त्वरित आपदा प्रबंधन के लिए कैसे उपाए होने चाहिए । पहाड़ों के अंधा धुंध दोहन को करोकने , विकास की सुसंगठित नीति बनाने और पहाड़ों की सुरक्षा के लिए जो रणनीतिक प्रबंध होने चाहिए वह हुए ही नहीं । यदि नदियों के किनारे निर्माण प्रतिबंधित होता तो इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद जन-धन की इतनी हानि नहीं होती । इस अनियोजित विकास के साथ ही जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी पहाड़ की दुर्दशा के अहम कारणों में से एक है ।

उत्तराखंड में राहत गतिविधियों की स्थिति देखकर अंदाजा लग रहा है कि भारत आपदाओं से निपटने में अब भी कितना अक्षम है । यह भी सही है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अमेरिका जैसा साधन संपन्न देश भी मजबूर हो जाता है लेकिन अपने देश में यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपदा से निपटने की तैयारी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता । आज हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में एक के बाद एक सरकारों से यह सवाल पूछना एकदम जायज है क्या उन्होंने ऐसी मंजूरियां दी जिससे यह इलाका बाढ़ और भूस्खलन के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हो गया ।

आज इस प्राकृतिक आपदा ने हिमालय क्षेत्र के विकास पर नए सिरे से सोचने का दबाव दिया है । आज पहाड़ों में पर्वतवासियों के जीवित रहने के लिए हिमायल की हिफाजत जरूरी है ।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** उत्तराखण्ड त्रासदी पर 193 के तहत चर्चा में निम्नांकित बिन्दु ले करना चाहता हूं ः-

(1) एमपीलैड के तहत जो राशि प्राप्त हुई है उसके लिए उत्तराखण्ड सरकार को एक पृथक से प्रोजेक्ट मंजूर करना चाहिए जिससे सांसदों का भी सहायता से एक पुनर्वास प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके । ऐसा एक अभिनव प्रोजेक्ट हो ।

(2) जो त्रासदी में मृत घोषित हुए हैं या लापता हैं उनके लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मृतक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए क्योंकि "डेथ सर्टिफिकेट" के बिना समुचित सहायता या समुचित राहत नहीं मिल पाती है ।

(3) जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या कंपनी है उसकी सीएसआर की राशि उत्तराखण्ड त्रासदी के पुनर्वास में लगनी चाहिए । ऐसा Mandatory Provision किया जाना चाहिए ।

(4) जिन राज्यों से उत्तराखण्ड सरकार को नगद राशि प्राप्त हुई है या जिन-जिन राजनीतिक दलों से राशि प्राप्त हुई है उनके नाम में प्रोजेक्ट पूरा हो तथा समयबद्ध सीमा में हो ।

(5) विज्ञान एवं तकनीक का सहयोग लेकर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था विकसित की जाए ।

(6) बीआरओ को समुचित राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि ग्रामीण सड़कों की भी Connectivity पूरी की जा सके ।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, उत्तराखंड की त्रासदी बहुत विकट हो गयी है और माननीया सुषमा जी व और सदस्यों ने काफी विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। लगता है दुनिया ही खतरे में है और सबसे ज्यादा खतरे में अपना देश है। हिमालय का क्षेत्र जो है उससे देश की अधिकांश नदियां निकलती हैं और उन नदियों का आज क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है। हम संकटों को बुलाते चले जा रहे हैं और आज जो स्थिति है यह खाली देवी-देवताओं से नहीं रुकेगी। आपने बहुत से देवी-देवताओं के नाम लिये और लोग तो हजारों सालों से इनके नाम लेते आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम से आपदाएं नहीं रुकेंगी, यह आपदाएं साइंटिफिक टैम्पर से रुकेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में या तो बिजली के प्लांट हैं या टूरिज्म हैं या फिर नदियां हैं। उत्तराखंड की त्रासदी को देखकर उसका कोई हल हिमालय को बचाने के लिए निकाला जाना चाहिए। हालात यह है कि जिस समय यह त्रासदी हुई, देश हड़बड़ा गया और अपनी स्थिति के अनुसार हम लोगों ने वहां फौज की मदद से इंतजाम किया। दुनिया भर में आजकल फौज इस काम में आगे आ रही है। फौज के जो लोग शहीद हुए हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उन्हें ठीक मुआवजा मिलना चाहिए। मैं पूरे देश में घूमता हूं और मैं स्वयं जानता हूं कि अभी तक कोई हिसाब-किताब, जो सरकार की तरफ से घोषित हुआ वह तो राज्य सरकार ने दे दिया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता जो पहुंचनी चाहिए, वह नहीं पहुंची है। उस काम में जरूर विलम्ब किया जाता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे इलाके में कोसी में त्रासदी आई थी और उसे संभालने में कुछ समय लगा क्योंकि हिंदुस्तान के पास ऐसे इंतजाम नहीं हैं और त्रासदी के समय तो

अमरीका भी सिर झुका देता है। जिस सभ्यता को सबसे ऊंचा मानते हैं, उसी सभ्यता ने यह सारा काम शुरू किया है। हम उनकी नकल कर रहे हैं। प्रकृति के साथ मेल का हमें जो सबक मिला था, वह महात्मा जी ने दिया था। इस देश की कोई खूबी थी, तो वह थी कि हम प्रकृति के साथ दोस्ती रखते थे। प्रकृति के साथ दोस्ती से यह देश सदियों से ज्यों का त्यों खड़ा है। आज हमने इतनी छेड़खानी कर दी है, चारों तरफ देश की नदियों से रेत निकाल रहे हैं, चारों तरफ नदियों को एक जगह नहीं, दस जगह, बीस जगह उसके गले को बांध रहे हैं। नरौदा के बाद गंगा में हिमालय का एक बूंद पानी नहीं आता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपए की सहायता से वहां के लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। वहां आदमी वैसे ही बहुत दिक्कतों में रहता है। ऊंचे पहाड़ों में रहता है और वहीं खेती करता है। वहां बहुत मश्किलों से लोगों का जीवन चलता है। उनके जीवन में जो थोड़ा-बहुत सुख था, वह भी छिन गया है। अब उस छिने हुए सुख की सरकार को जल्दी से जल्दी भरपाई करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिमालय के साथ इस देश का पूरा आने वाला भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हिमालय नीति बननी चाहिए। दुनिया के दूसरे देश बच जाएंगे, लेकिन अगर हिमालय नहीं बचा, तो यह देश नहीं बचेगा। यह देश दो तिहाई चला जाएगा। सारी नदियां हिमालय से निकल रही हैं। ग्लेशियर पिघल गए, गंगा ही पीछे हटती जा रही है लेकिन हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है। हां, हम लोग हाय-तौबा जरूर मचा रहे हैं। अब यह जो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, इस पर हाय-तौबा जरूर मचा रहे हैं। एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह त्रासदी हमने खुद बुलाई है। दुनिया के जो इंसान हैं, जानवरों ने, पक्षियों ने प्रकृति को नहीं बिगाड़ा, प्रकृति तो इंसानी कौम ने बिगाड़ी है। बेला-ठेला, यानी जो भी हो सकता है, किसी तरह से भी हम नदी के साथ छेड़खानी करने को तैयार हैं, हम मानते ही नहीं हैं। हम पूजा करते हैं लेकिन उस पूजा के अनुसार हमारा व्यवहार ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिमालय नीति बननी चाहिए। हिमालय की नीति बनने से देश की सुरक्षा से लेकर इस देश की आने वाली परिस्थिति ठीक हो सकती है। हिमालय बचाना है तो नदियां बचाओ। हिमालय बचाना है तो हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी वाला, ऐसा सदियों में कभी हिमालय में तबाही नहीं हुई। हजारों-हजार बरस से हिमालय खड़ा है। लोग सुकून के लिए वहां जाते थे, लेकिन वहां अब व्यापार के लिए जा रहे हैं। पहाड़ को खोद रहे हैं, अलग कर रहे हैं मिट्टी को। हम सड़क बना रहे हैं तो उसका कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। बांध बना रहे हैं तो उसका कोई साइंटीफिक तरीका नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए, हिमालय नीति बननी चाहिए और हिमालय पर एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए और मिनिस्ट्री का काम है हिमालय को पहले बचाओ। यदि हिमालय को नहीं बचाओगे तो यह देश नहीं बचेगा, किसी कीमत पर नहीं बचेगा। उत्तराखण्ड ही नहीं, उत्तराखण्ड की तबाही आने वाले इतिहास को एक तरह से दिखाता है कि आने वाला इतिहास में अंधेरा है, डूबने वाला है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हिमालय की नीति बनाओ और हिमालय की नीति बना कर के इस देश को बचाने का काम करो। बिजली आ जाएगी लेकिन यह पानी कभी नहीं आएगा। पानी चला गया तो जीवन चला गया। जल ही जीवन है और यदि जल ही हमने नाश कर दिया तो फिर धरती बचती नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं लंबे तौर पर नहीं बोलना चाहता हूं, मैंने आज तैयारी भी नहीं की थी, अचानक मुझे बुला लिया गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

MR. CHAIRMAN : Members, who want to lay their speeches, can do so.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the disaster that took place in Uttarakhand in the month of June. You are a representative of those areas and your speech was anguished today and I felt that the pain of the people is reflected. Maharani of Tehri Garhwal is also here. She represents those people, particularly Chamoli, Uttarkashi and Pithoragarh. All these districts are affected. The main two *dhams*, Kedarnath and Badrinath were severely affected.

Today we have three things to do. It is almost three months or two-and-a-half months since the disaster took place. One should really ponder over the causes of the disaster because it was a wake up call. Geologists and everybody knows that Himalayas are a seismically and ecologically sensitive zone and it is based on tectonic plates, which rest on one another. So, earthquakes and landslides can take place at any time.

But what have we done? Experts say that massive deforestation, violation of all construction norms in hydro power projects, of which there are 336 operational hydro power projects in Uttarakhand, and complete absence of disaster management plans led to the massive scale of destruction in the Himalayas. Also, there is human greed where we lived on the course of the rivers where in a State of one crore people, there are 2.5 crore pilgrims. This total thing needs to be looked into and there should be controlled access of people to places of pilgrimage and tourism. Like for Mansarovar, every year the Government regulates the number of pilgrims. There should be also some control on the entry of pilgrims. All of them go with pious wishes but they cannot violate the ecological norms.

The scale of devastation is massive. In a reply to a Parliament Question given on 6th August, it has been stated that the number of human lives lost is 540; number of missing persons is 5474; number of houses damaged 4726; and number of persons rescued to safer places 108000.

Now, the main thing is that two institutions were found lacking. One was the Uttarakhand Government which did not

have a disaster management programme in place. The second organization which failed was the NDMA, National Disaster Management Authority, headed by the Prime Minister. It was found that it had no immediate response to the whole problem. Had it not been for our Armed Forces and Para-Military Forces, the disaster would have been total, and I give my salute to the members of the Armed Forces who risked their lives. You know that in an helicopter accident, so many IAF personnel were killed. I pay my tribute to them. The best performance was by the IAF which deployed 45 helicopters and rescued 23775 persons. They are the best. The NDRF, National Disaster Response Force, rescued 9500 people.

ITBP, Indo-Tibetan Border Police, which patrols the Indo-China Border in Maharani's constituency, rescued 33,000 persons. The Indian Army deployed 8000 personnel and 12 Army helicopters. They evacuated about 12,000 persons. Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi formed five rescue teams, one of which was headed by Bachendri Pal, the Everester, and they rescued 6,500 persons. If it was not for these specialised organizations, the disaster would have been more massive.

Sir, the other point I want to make is that the Prime Minister, after his aerial survey, sanctioned Rs.1,000 crores for the relief and rehabilitation work. The kith of each dead person was given an amount of Rs.5 lakh. It seems that they have accepted the recommendation that those missing persons, who are registered missing, their families will also get Rs.5 lakh, which is a good thing.

Now a massive reconstruction exercise should be started. But, it does not mean that immediately you allow all the hotels and big houses which were built on the site of Alaknanda and Mandakini, should be allowed. Very carefully, the Uttarakhand Government should now control new construction and a proper attention should be paid on it. I think, Sir, the at national level, a conference should be called with top geologists in the world, who should discuss as to what the way should be to maintain the sensitive zone of Uttarakhand. It is absolutely necessary. It is a national disaster. These are the holiest places for Hindus. Therefore, it is necessary to preserve them as well as the nature and the lives and security of the Uttarakhand people.

Sir, I shall conclude by saying that you asked the hon. Members of Parliament to contribute money from their MPLAD funds for this cause. I can humbly state that I contributed Rs.20 lakh from my MPLAD fund for Uttarakhand reconstruction and Rs.1 lakh to the Prime Minister Relief Fund from my own income. But, only 223 MPs have come forward. Through you, Sir, I appeal to all MPs – there are 800 MPs and odd – that they should contribute at least Rs.10 lakh for relief and rehabilitation work. An amount of Rs.50 lakh by each MP from his MPLAD fund is allowed. They should at least contribute Rs.10 lakhs for this purpose. Only 223 MPs have come forward for this, which I find very little. We should all unite to rehabilitate the Uttarakhand people. And, I hope, Sir, before long under your stewardship, Uttarakhand finds back its normal life. Their cattle – you were mentioning even mules – died because they could not get food. All these people who have lost cattle, who have lost mules, should be rehabilitated and normal life should start again in Uttarakhand. We should learn from the mistakes of the past. Our human greed should not destroy the Himalayas rather a considerate approach towards rebuilding of the Himalayas should be started.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Mr. Chairperson, I am very much thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Discussion under Rule 193, regarding Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand.

Sir, it is really a shocking incident that had happened in the holy land. My heart beat increases while I recapitulate the pictures and sceneries that we have seen in various media. While speaking on this issue related to the devastating natural calamity of Uttarakhand, think of those who have experienced this disaster personally there in Uttarakhand.

Hats off to the Army personnel, paramilitary forces, Indian Air force and other allied agencies, who have made it possible and saved thousands of helpless people and their valuable lives, while thousands of children, men and women, elderly people have gone to the pilgrimage of Badrinath, Uttarkashi, Gangotri, Yamunotri and other places.

During the relief and rescue operation, due to the bad weather and heavy rainfall, there was a tragic incident of a helicopter crash in which one Army Officer from Tamil Nadu lost his life. I honour the memory of these people.

Our hon. Prime Minister visited Uttarakhand to take stock of the situation on 19th June. He announced assistance of Rs.1,000 crore to the State. That is not enough; more funds need to be allocated by the Central Government.

I would like to add one point that after every big disaster happens we debate it for a while. But, this is very alarming and a wake up call for all of us. I would like to recall the disaster caused by tsunami in 2004 when thousands of innocent lives were lost. We are being hit by one after another disaster in various parts of our country.

On this occasion I would like to emphasize on the disaster caused by sea erosion. In my constituency 47 villages are in sea-shore area. All over India, thousands of villages are in sea-shore areas. Due to sea erosion, sea water enters into villages causing massive loss to the lives of people including destruction of houses, land, crops, animals and other valuables. Due to disasters like sea-erosion, a number of people belonging to the fishermen and other communities die or their families are severely affected. I would like to draw the attention of the Government that no relief and rehabilitation operations are carried out by the Government after these disasters strike. I urge upon the Government that sea-erosion must be declared as a natural calamity and it should figure in the list of natural calamities. The fishermen go deep into the sea and in case any disaster occurs, they lose their lives. To deal with such cases, adequate welfare measures and schemes should be launched by the Government.

The fishermen families do not even get the death certificate when they go to deep sea for fishing and lose their lives. Death certificates should be issued to them within a period of six months to one year. Now it takes seven years for the Government to give the death certificate after the death of a fisherman.

In Tamil Nadu, whirlwind is causing damage to cash crops like banana. When banana plants are destructed due to whirlwind, its cultivators suffer a huge monetary loss. Since whirlwind does not come under natural calamities, the Central Government is not allocating funds to the State Government. Therefore, I would like to urge that whirlwind damage should come under the head of natural calamities.

I would like to say that cutting across party-line, we must together rise to the occasion setting aside our differences and affirm our commitment to the welfare and wellbeing of the people of Uttarakhand and also those who are affected by the natural disasters.

प्रो. सौगत राय : सर, केदारनाथ और बद्रीनाथ आपकी कॉन्सिटयूंसी मे हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हाँ। यमुनोत्री गंगोत्री इनका है।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, please permit me to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Okay, you are permitted.

SK. SAIDUL HAQUE : We all know about the tremendous devastation, death and destruction that happened in Uttarakhand, due to cloudburst, landslide and also flash floods. We know that Kedarnath, Gaurikund, Badrinath, Rudra Prayag were severely devastated.

I congratulate the Indian Army, Indian Air Force, ITBP and Border Road Organisation for doing tremendous work. But I wonder, what is alarming is that the State Government is callous to face this situation. I am saying this only because of the slow pace of rescue operations. When the Chief Minister was heckled by a group of women, only then he admitted that the State was not prepared to face this kind of a tragedy.

Not just that; the irony of the situation is that 48 hours before the disaster happened on June 15th, on June 13th the Regional Meteorological Centre in Delhi forecast heavy rains across Uttarkhand. But the State Government paid no attention to it. There was a warning from the Meteorological Department, but the Uttarakhand Government issued a warning only on 16th, that is, after two days and took the help of the Indian Army on 18th. So, two days passed in-between that also. Had it been done earlier, so much of devastation could have been avoided.

Not only the present Congress Government, but I also accuse the previous BJP Government. It is because the previous BJP Government and the present Congress Government ignored the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem which was launched in 2008. Here, I would also refer to the 2008 report of the C&AG. That report categorically told about the rampant destruction of the Garhwal Himalayas and cautioned that it would bring about a great environmental impact.

I would tell what happened during the tenure of the BJP Government and the present Congress Government. They allowed to have 242 hydro-electric projects out of which 42 are already in operation while 200 are in the pipeline which would be built on the Bhagirathi and Alakananda Rivers. What is more interesting is that 70 hydel projects are proposed on the two main tributaries of the Ganga-Alakananda and the Mandakini and two 20 kilometre long tunnels are being built to

divert the flow of these rivers for hydel projects, and constant blasting of riverbanks has affected the local ecology. That is not all. The green cover in the hills that checks and absorbs the flow of water has been eroded in the name of hydel energy. So, by what they did in the name of development, they invited death and destruction. So many geoscientists and environmentalists had talked about this kind of a thing, but both the Governments paid no attention to check it so as to maintain the ecological balance.

In fact, landslides are a regular feature in Uttarakhand. I am quoting from ISRO. After the Malpa (Pithoragarh) tragedy in 1999, ISRO told that landslides are a regular feature in Uttarakhand. In 1970, there was a landslide in Alakananda Valley. In 1978, Kanodiya landslide took place. In 2003, Varunavat Parvat landslide happened. In 2009, Munisiyari landslide took place. In 2010, large scale landslide took place in the State. In 2012, landslide in Uttarkashi and flash flood in Ukhimath took place.

All these events of the history tell us that this zone is vulnerable to such calamities, but there has not been done any local planning or local effort to control them. A number of hotels and residential and commercial buildings have been built without proper planning. The number of cars, jeeps and taxis increased more than six times. The total population of Uttarakhand is about one crore while the number of tourists and pilgrims visiting the State is almost 2.5 crore each year. This unchecked construction of buildings and increase in the number of tourists led to damage of ecological system in the area of the Bhagirathi River and the Alakananda River.

The Central Government cannot shirk its duty. I say this because the Central Government had assured the Supreme Court that it would not allow construction of any dam within 135 kilometres of the Ganga. In spite of that, 70 dams had been built within a distance of 150 kilometres of the Alakananda and the Mandakini. So, the Central Government also cannot shirk its duty. It is need of the time that there should be development and there should electricity, but it should not be at the cost of death and destruction.

Now, I come to relief and rehabilitation. The Prime Minister has already announced a relief of Rs. 1,000 crore. All the CPI (M) Members of Parliament, from this House as well as the Upper House, have given Rs. 50 lakh each from the MPLADS. We are ready to donate more for the relief and rehabilitation work, but the question is what the Ministry of Home Affairs is doing. The Home Ministry is the nodal Ministry for providing financial assistance. They have constituted the National Disaster Management Authority. They have also established the National Disaster Response Fund, Distress Response Fund and National Disaster Mitigation Fund, but what is the Central Government doing in the case of both the NDRF and the SDRF? The Central Government should provide 70 per cent for NDRF. It should provide 90 per cent in the case of special States. But the Central Government is not doing its action.

My last point is about the National Disaster Management Authority whose *ex officio* Chairman is the Prime Minister himself, but there is lack of performance on the part of the NDMA. The Uttarakhand tragedy has exposed its defunct status. It needs to be addressed because C&AG presented its Report on Disaster Preparedness in India in April, 2013. What is the C&AG's observation? It says,

"1. No national plan for disaster management was formulated till date;
2. None of the major projects undertaken by NDMA have been completed;
3. National Disaster Mitigation Fund not yet established;
4. Communication system for disaster management not developed;
5. Effective national disaster response force has been hampered for shortage of trained manpower and training facilities."

That is why I am calling the attention of the House, through you, Sir, to the fact that both the National Disaster Management Act, 2005 and the National Policy on Disaster Management, 2009 have not been properly implemented. This House, in the past, has discussed the issue of pollution of the Ganga River twice. The Standing Committee on Water Resources has also discussed this issue, but it has not yielded any results.

That is why I urge upon the Government to take appropriate action so that such kinds of incidents do not happen in the future.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for this opportunity. I stand here today to participate in the discussion on the Statement made by the hon. Minister of Defence regarding Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand raised by Shrimati

Sushma Swaraj on 30th August, 2013.

At the outset, I would say that one does not need an Usain Bolt to predict that India's response time is poor. The disease spreads across the board and in almost every sphere. Little wonder then that when disaster strikes, all we manage to do is indulge in blame game.

Had we been a little bit proactive, a number of lives could have been saved, along with it property worth crores. But neither the National Disaster Management Authority nor the Uttarakhand Government chose to act when the country's premier scientific body, ISRO, sounded the alarm bells. An alarm was sounded out by ISRO's MOSDAC (Meteorological and Oceanographic Satellite Data Archival Centre), a facility set up to promote the exchange of satellite data, on the day the disaster struck.

Unfortunately, both the NDMA and the State Government authorities chose to sleep over the highly important alert. This MOSDAC alert was sounded a good 16 hours before the monsoon came down with all its fury, but it failed to get the authorities into action mode. MOSDAC showed clearly that eleven places were feared to be affected by severe rain and cloud burst and listed Barkot, Kirtinagar, Muni-ki-Reti, Pauri, Raiwala, Rishikesh, Rudraprayag, Srinagar, Tehri and Uttarakashi. NASA had also predicted 25 days before through a satellite picture that the Chorabari Glacier's soft ice is melting very fast, but Indian scientists could not gauge the devastation that it may cause.

When warnings are there stating heavy to very heavy rains coupled with landslides at places, is it not enough to suggest that there is going to be crisis of this magnitude? It is beyond debate, the debate that the mountainous terrain is inherently risky and because of its proximity to Himalayas is extremely prone to sudden changes in weather. Between 15th and 18th June, Uttarakhand saw an unusual 261 centimeters of rain, when the State normally gets only 16 centimeters of rain through the whole month of June. What is surprising in this entire episode is that there is lack of preparedness to deal with a disaster of this magnitude.

The Indian Armed Forces played a heroic role in rescue and evacuation, but several official agencies were found to be lacking in their job. What has become apparent is that the civilian administration has been less than responsive. National Disaster Management Authority needs to be revamped. Their inadequacies have been exposed in almost every emergency they have tackled, Uttarakhand being the most glaring example. We need professionals with experience in different fields.

The interface between NDMA and the civil administration also needs to be better structured and better tuned. In our country, the level of preparedness for disaster management is extremely uneven and requires considerable strengthening. Since the civil administration remains ill-equipped for undertaking quick response to major disasters, the armed forces have been the primary option to handle major disasters. The involvement of the armed forces in disaster response and relief operation is important in civil-military relations. Efforts should be made for using the expertise of the armed forces to bolster the capacity of the civil authorities including the disaster response forces. It should achieve self-reliance and thus, reduce the dependence on the armed forces. The Department of Disaster Management should not be the changed name of Department of Relief and Rehabilitation, Home Guards and Emergency Fire Services with *ad-hoc* personnel. It should work like a crack-team.

Sir, we are informed that a Task Force set up to review functioning of the NDMA has submitted its Report to the hon. Home Minister recommending changes to the Disaster Management Act, 2005 which governs NDMA. What have they suggested? They have said that it is necessary to slim down the body and there is an urgent need to integrate it with other Government agencies to ensure smooth coordination and accountability. The C&AG has very recently come down very heavily in the functioning of NDMA and the report says and I quote:

> "The performance of NDMA in terms of project implementation had been abysmal. So far, no major project taken up by NDMA has been completed. It was noticed that NDMA selected projects without proper ground work and as a result, either the projects were abandoned mid-way or were incomplete after a considerable period".

Lastly, Sir, I would say that there are two practical steps the State of Uttarakhand Government need to take to prevent occurrences in future. One, it needs to create a pilgrim and tourist management system and two, it ought to devote more attention and money to regulating tourism infrastructure to service tourists, hotels, shops, parking lots, and mini-malls which have come up, not just on road side but even on river beds, crumbling slopes and forest areas. There is a need to have a regulatory body to oversee land use. The Uttarakhand population is 1.08 crore and as per the Ministry of Tourism, tourist arrivals are 2.5 crore. This is a recipe for disaster. Builder's greed has led to nature's fury. Rampant construction has

brought this disaster. One of our eminent engineers Shri Bishnu Prasad Das who is known throughout the country has written an article very recently on 31st August, 2013 in *The Hindu* that the devastating landslides that have occurred were caused by the undercutting of the fragile hill-slopes for highways rather than by dams which actually helped to mitigate the floods. I read that small portion though it is a big article.

> "On the contrary, the Tehri reservoir on the Bhagirathi held back the incoming devastating flood which attained a peak of 7000 cubic meter per second and since the release was restricted to a mere 400 cubic meter per second causing the reservoir to rise by 25 meters a day, the flood damage below the Tehri dam was minimal. Without the Tehri dam, the combined flood of the Alkananda and the Bhagirathi would have exceeded 35,000 cubic metre at Rishikesh possibly wiping out the prosperous urban river stretch at Rishikesh, Haridwar and Saharanpur."

This needs to be stressed upon. There is an idea that is being quoted that dams are actually the culprits. But what this engineer has stated here is that it has protected these three major urban areas besides the banks of River Ganga. The path ahead should be to learn lessons by an informed debate. The immediate need is to enforce flood plain zoning below Rudraprayag on the Alkananda and Maneri Bhali on the Bhagirathi and disallow permanent structures in flood prone zones.

Finally, I would say that three 'R's should always be kept in mind -- first, is Rescue followed by Relief which should be followed by Reconstruction and Rehabilitation. The National Disaster Response Force should work in tandem with the State Disaster Response Force. With these words, I conclude.

* **SHRIMATI PRATIBHA SINGH (MANDI) :** I would like to express my views on the matter of urgent public importance concerning my state, particularly my Parliamentary constituency.

The state of Himachal Pradesh has suffered unprecedented loss on account of untimely and heavy monsoon rains this year. The districts of Kinnaur and Sirmaur, which are adjoining to the state of Uttrakhand, were severely affected during the fury unleashed by rain, cloudbursts and even heavy snowfall from 15th to 17th June, 2013. Besides these districts, whole of the State was also affected by the unprecedented rains in particular district Mandi, Kullukangra and Shimla. As per the data of the Indian Meteorology Department, during the monsoon, compare to the other years, the rainfall was 576% to 1358% above normal, has been recorded for these three days.

Timely intervention by the State administrative machinery ensured minimal loss of life, and effective relief and rescue operations were carried out. Still the loss to private and public property has been immense. People in the affected areas have lost their houses, agricultural lands, standing agriculture and horticulture crops, including full-grown orchards thus shattering the rural economy and livelihoods. About 10,000 houses have been either fully or partially damaged in the State; and even the partially damaged ones are not habitable. More than 64 persons have lost their lives during this natural calamity. Public infrastructure especially roads, water supply, irrigation schemes, electricity infrastructure, community assets etc. have been badly damaged requiring years of investment to restore it back to normal.

The state has submitted a detailed memorandum seeking central assistance to the extent of Rs.1972.08 crore for relief and rehabilitation under the National Disaster Response Fund. This memorandum was given to the Government of India in the first week of July. The central team too has visited the state and assessed the situation, but assistance from NDRF is still awaited. The attention of this august House is drawn towards this issue of extreme importance in Himachal Pradesh and to deliberate on the steps being taken or planned by the Government of India to ensure rehabilitation of the affected people of the State and restoration of damaged public infrastructure.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदय, आपने उत्तराखण्ड के इस विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रथम, जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई, जिनकी जानें गयीं, जो जवान शहीद हुए, उन सभी को मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं। आपको शायद याद होगा कि आप ही के माध्यम से इस आपदा के पन्द्रह दिन पहले मैं अपने परिवारजनों के साथ वहां गया था। घटना होने के बाद जिस दिन मैंने उसे टीवी पर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यही वह जगह है जहां पन्द्रह दिनों पहले मैं गया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं कितने हजार लोगों की वहां मृत्यु हुई, लेकिन जो भी हुआ, बुरा हुआ। यह कहते हैं कि इंसान धरती पर आता है और उसे यहां से जाना भी पड़ता है। लेकिन वह इस तरीके से जाएगा, शायद किसी ने यह सोचा नहीं होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ के जो अध्यक्ष हैं, वहां के जो विधायक हैं गणेश जी, उनके साथ मैं वहां चला गया था। वहां दर्शन होने के बाद और हमारे पूरे परिवार के वहां से आने के बाद जिस तरह यह आपदा हुई, जिस तरीके से वह क्षत-विक्षत हुई है, उसे देख कर यह लगता नहीं कि यह वही जगह है। जैसे आप ने अपने वक्तव्य में कहा कि उसे बहुत ही तादाद में ताकत देने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि वहां इंसानों के साथ जानवर भी मृत हुए और उनका पता नहीं है। मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो शायद तीस हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की वहां आर्थिक मदद की जरूरत है। मेरे ख्याल से महाराजा जी के इलाके में गंगोत्री-यमुनोत्री हैं और आपके इलाके में केदारनाथ, बद्रीनाथ है। ये दोनों जगह हमारे हिन्दू धर्म के हिसाब से, हिन्दुस्तान के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती है कि ये जो स्थान हैं, जिन्हें हम उत्तर भारत के चार धाम कहते हैं, इसे आगे के सैंकड़ों-हजारों साल तक आबादी के रहने के लिए इसका मास्टर प्लान बनाएं। आपने जैसा कहा कि सही मायने में आगे आने वाली स्थिति को ध्यान में रख कर, हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ के मंदिर का जब निर्माण हुआ होगा तो शायद ऐसा सोच कर ही बनाया गया होगा क्योंकि अगर आप उसकी दीवारों को देखिए तो बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानों के आने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उसको हटाने में शायद दस-पन्द्रह साल भी लगेंगे। मैंने खुद देखा कि कुछ नदियों का रूप भी बदल गया है। मैं समझता हूं कि इस चीज़ को देखने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक मास्टर प्लान बनाएं। जैसे यह कहा गया कि वहां जो हेलिकॉप्टर जाता है, उसके लिए वहां कच्चे हेलिपैड बने हैं। वे पर्याप्त नहीं हैं। पहले यह कहा जाता था कि चार धाम यात्रा करने में दस-पन्द्रह दिन लगते थे। मैंने डेढ़ दिन में चार धाम यात्रा की। उस से हजारों की संख्या में लोग वहां आ रहे हैं। मेरी विनती होगी कि सरकार को इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने लोग वहां किस दिन आने वाले हैं, कितने लोग वहां से केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, वहां से यमुनोत्री जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे। इसकी वज़ह से हमें आज पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग वहां आए, कितने लोग वहां थे और कितने लोग मृत हुए? आज उनका कोई अता-पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक ठोस कदम हमारे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से होना चाहिए।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आप ने बहुत मदद की है। जिन-जिन लोगों ने मदद की है, मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वहां जो गांव हैं, हम ने देखा कि वहां 25 घर, 40 घरों को मिला कर छोटी-छोटी बस्तियां हैं, आप को उन्हें एक जगह पर ला कर एक हजार, डेढ़ हजार, दो हजार घर करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी आपदा भविष्य में हो जाए तो उससे बचने के लिए सरकार को इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी आपदा के लिए वहां बड़े गोदाम बनाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले भविष्य में लोग वहां भुखमरी से न मरें। इसी तरह से जैसा आप ने कहा कि फन्नीकुलर लगाया जाए तो यह लगाना जरूरी है। अगर हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा यात्री आ सकेंगे क्योंकि हम रहें न रहें, जब तक ये धरती रहेगी तब तक वे धाम रहने वाले हैं।

20.00 hrs.

मैं समझता हूं कि आगे के सौ साल, दो दौ साल, पांच सौ साल इस तरीके से फन्नीकुलर की जरूरत है, जिससे ज्यादा यात्री भी आ सकते हैं और वे दर्शन भी कर सकते हैं। वहां पर बहुत सी जगहों से श्रद्धालु आते हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि वहां मंदाकिनी नदी से सबसे ज्यादा खतरा है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, उसका प्लान अच्छी तरह से करना पड़ेगा। मैं वहां आने वाले भविष्य की बात रखते हुए केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि आप पैसे जरूर भेजेंगे, लेकिन प्लान बनाने के लिए ज्यादा संख्या में वहां उसकी प्लानिंग करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इन सब चीजों को रखने के लिए पांच साल, दस साल लगें, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, ये न देखते हुए, यह हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान है, इसको देख कर आप उसके ऊपर गौर करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Hon'ble Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak in the discussion on natural disasters in Uttarakhand under Rule 193. The State of Uttarakhand has so many tourist centres. Large number of tourists from all over the country and abroad visit Uttarakhand every year. The Union and Uttarakhand State governments are responsible for planning and providing basic infrastructure facilities including lodging, transport, road and medical facilities to the visiting tourists and pilgrims. Uttarakhand witnessed a natural disaster of such a huge magnitude and destruction was so unprecedented due to unplanned activities and shortcomings in providing basic infrastructure and amenities in the State. Thousands lost their lives. Large number of people lost their belongings. Losses incurred in the State of Uttarakhand due to natural calamity amounted to several thousands of crores of rupees. While overcoming such a natural calamity the State concerned and the Union government have together failed to undertake relief measures efficiently. It is a matter of concern. Tourists were stranded for so many days in many places of Uttarakhand without proper food, clothing, medical facilities and even without any hope of returning to their respective native places. I also wish to state that Union government had not instantaneously undertaken the relief and rescue measures in the State of Uttarakhand. As soon the information regarding stranded tourists belonging to Tamil Nadu was received, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma had sent a team headed by the Tamil Nadu State Revenue Secretary immediately to the disaster-affected Uttarakhand. This team stayed in Uttarakhand for 15 days. Pilgrims from Tamil Nadu, who were stranded in Uttarakhand, were airlifted and sent to Delhi. These pilgrims were then made to stay in a camp set up with helpline facilities in Tamil Nadu House, New Delhi. The government of Tamil Nadu had provided food, accommodation and air travel

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

to Tamil Nadu free of cost to all such pilgrims. Not only pilgrims from Tamil Nadu but also the pilgrims of other States were also helped by the government officials of Tamil Nadu ensuring their safe return to their respective native places. I also recall that an helicopter pilot named Mr. Praveen sacrificed his valuable life while engaging in rescue work in Uttarakhand. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththlaivi* Amma is a towering personality who remains a frontrunner among

leaders of the world. She has displayed swift action and efficiency at a time when natural calamity of such a huge magnitude struck. When disastrous *Tsunami* struck Tamil Nadu, there was huge devastation in the State and Hon. Chief Minister Dr. *Puratchiththalaivi* Amma undertook several relief measures in a laudable way which were appreciated by world nations. Former US President Mr. Bill Clinton had felicitated Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma in this regard. The government of Sri Lanka had also invited a team of government officials from Tamil Nadu to visit their country to impart training on successful implementation of relief work. Union government should have taken relief and rescue measures in the State of Uttarakhand soon after such a devastating disaster. At the time of such a natural disaster that had taken place outside Tamil Nadu, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Dr. Puratchiththalaivi* Amma with utmost generosity had donated Rs. 5 Crore as immediate financial aid to the State of Uttarakhand. Union government should work in such a way to mitigate the destruction caused by natural disasters. In Tamil Nadu when farmers were affected due to drought like condition and their crops were damaged, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchiththalaivi* Amma announced a financial assistance of Rs.15,000/- per acre to each of the drought-affected farmers. Union government has not still provided crop insurance amount to Tamil Nadu. I urge that the Union government should take necessary action to release the crop insurance assistance that is due to the State of Tamil Nadu.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्मम): महोदय, आपने जो मुझे उत्तराखण्ड के बारे में बात करने का मौका दिया है, उसके बारे में हम आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब उत्तराखण्ड का डिजास्टर हुआ था, इस ऑपरेशन में 9 दिन हम उन सब लोगों के साथ थे। इसलिए हमको कम से कम 9 मिनट इसके ऊपर बात करने का मौका दीजिए।

महोदय, जब इस तरह का डिजास्टर हुआ, काफी एक्सपर्ट्स और टेक्निकल लोगों की तरफ से कई तरह की बात सामने आयी हैं। उसमें बहुत लोगों ने तो इसे मैन मेड डिजास्टर कहा है। बहुत लोगों ने इसे फ्लड ऑफ दी पॉलिसी फेल्योर कहा है, मगर जो भी हुआ है, वह हुआ है। इस तरह से जब डिजास्टर होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीएमए की होती है, मगर वह भी पूरा फेल्योर हो गया। एनडीएमए के चेयरमैन हम लोगों के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए, उत्तराखण्ड दिल्ली के बगल में होते हुए जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसमें यह गवर्नमेंट टोटली फेल हुयी है।

चेयरमैन साहब, आपकी बात का ईच एंड एवरी वर्ड हमने सुना। एक तो आपने उत्तराखंड के बारे में कहा, दूसरा आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम आपके साथ एग्री नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी और प्राइम मिनिस्टर वहां गए। प्राइम मिनिस्टर केवल एरिया का सर्वे करके आए। आज के दिन आप बोलेंगे कि वहां एक मिनिस्टर की कमेटी बना दी है, अभी वह यह सब देख रही है। ये मिनिस्टर उस टाइम में उत्तराखंड में जाकर देहरादून में क्यों नहीं बैठे हैं? आज के दिन देश में यह सबसे बड़ा डिजास्टर है। लाखों लोग इसमें प्रभावित हैं। पार्लियामेंट के अंदर इसी सैशन में जो क्वैश्चन दिया था, उसका आंसर देखा तो पता चला कि सोलह सौ गांव प्रभावित हुए हैं, उसी तरह से आज भी 5,474 लोग मिसिंग हैं। आज भी उनको लोकेट नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हजार करोड़ रूपए एनाउंस किया तो सब लोग सोच रहे थे कि एक हजार करोड़ रूपए मिल गए। स्टेट गवर्नमेंट ने जो 13 हजार करोड़ रूपए की डिमांड की है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट तीन परसेंट भी नहीं दे पायी। 13 हजार करोड़ रूपए की जो डिमांड है, वहां 13 हजार करोड़ रूपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन वहां मात्र 395 करोड़ रूपए अभी तक रिलीज किए गए। एक दफा 250 करोड़ रुपए दिया और दूसरी दफा 145 करोड़ रुपए दिए। ये पार्लियामेंट में प्रश्न का उत्तर लिख कर दे रहे हैं कि जो भी स्टेट के लिए चाहिए हम लोग पूरी मदद करेंगे, फाइनैंशियल सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, इसी सत्र में 13.08.2013 को प्रश्न का जवाब आता है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना अफेक्टेड होने के बाद भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आंख नहीं खोली है। सभापति महोदय, यह घटना 16 तारीख को हुई थी। हम और हमारे नेता चन्द्रबाबू नायडु जी दोनों मिल कर इधर दिल्ली में आए, तब तक कुछ लोग आंध्र प्रदेश के लोगों के ले कर दिल्ली में आए। सबसे ज्यादा पिलग्रिम्स आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश के 2,780 पिलग्रिम्स उस समय स्टक अप हो गया। हमारे यहां स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है, हम लोगों ने सोचा था कि ये तेलुगू लोगों को बचाएंगे। यह घटना 16 तारीख को हुई है। हम लोग 23 तारीख को दिल्ली आए। दिल्ली के आंध्र भवन में उन लोगों को कोई खाना देने वाला नहीं था। छः-छः दिन तक महिलाएं स्नान नहीं कर पाई, ये आंध्र प्रदेश के भवन के रूम्स को ओपन नहीं करा पाए। हम लोगों को धरणा करना पड़ा। हम और चन्द्रबाबू नायडु जी ने रोड पर धरणा कर के आंध्र भवन में जितने भी रूम्स हैं, उनको खुलवा कर, उस समय 120 आदमी आंध्र भवन में थे, उन लोगों को रोड के ऊपर बैठाया गया था, उन लोगों को रोड के ऊपर खाना दे रहे थे। हम ने कहा कि कैंटीन को खोलो, छः दिन से इन लोगों को खाने के लिए नहीं है, नहाने के लिए नहीं है। हम लोगों ने रूम्स को खुलवा दिया। इसके बाद हम लोग देहरादून गए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से मिले। जिस तरह से आंध्र प्रदेश के कम से कम 3000 लोग इधर स्टक अप हो गए, उसी तरह से देश भर के पिलग्रिम्स वहां स्ट्रक अप हो गए। हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को बचाएंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : सभापति महोदय, हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है, यह इतनी दुख की बात है कि ऐसी घटना होने के बाद, सेन्ट्रल गवर्नमेंट में हमारे 13 मंत्री हैं, 30 आंध्रा कांग्रेस के एमपी हैं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मगर उन लोगों को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी नहीं कर पाए । पहली दफा हमने स्पेशल फ्लाइट डायरेक्ट लगा दिया। पांच फ्लाइट्स को लगा कर, आंध्रा के लोगों को हैदराबाद ले जाया गया, ट्रांस्टपोर्टेशन को अरेंज कर, हम लोग नौ दिनों तक उनके साथ थे। एक औरत के सर पर पत्थर पड़ने के कारण सर फूट गया था, और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी वह छः किलोमीटर चल कर आई। एक 70 साल का वृद्ध भी है, वह छः दिनों तक, जहां घोड़े रहते थे, वहां पड़ा रहा। ...(व्यवधान) अभी भी गवर्नमेंट को जिस तरह से केयर करना चाहिए, जिस तरह से अफैक्टेड पिपुल को प्रोटैक्ट करना चाहिए, इसमें टोटल फेल हो गई। बगल में सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हुए, कोई भी कन्सन्ट्रेट नहीं कर पाया। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट कन्सन्ट्रेट करती तो हम लोग बहुत लोगों को बचा लेते, उन्हें बचाने के बहुत चांसेज थे। मगर गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से पूरे देश से जो पिलग्रिम्स आए थे, उनमें से बहुत लोगों की मौत हो गई और बहुत लोग मिसिंग हो गए।

फाइनली हम यही बोलना चाहते हैं कि अभी कम से कम 13 हजार करोड़ रुपये की जो डिमांड है, उसमें से आपने सिर्फ 3 परसेंट, 395 करोड़ रुपये अभी तक दिए गए हैं, बाकी बैलेंस ये दे दें। सभापति महोदय, आपको मालूम है, बहुत सारे गांव बर्बाद हो गए हैं।

आखिरी में मैं यही बोलना चाहता हूं कि आगे भी इस तरह का फेल्योर नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये आगे के लिए पॉलिसी बना कर देश के लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, आज हम आपके माध्यम से यहां बहुत भीगी आंखों से उन सब परिवारों को सांत्वना देना चाहते हैं जिनके परिवार के लोग हंसते-खेलते घर से गए थे और वापिस नहीं आए और शायद कभी भी नहीं आएंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। जिस पर गुजरती है वही इसे जानता है। मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा। यह एक प्राकृतिक आपदा थी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत हिम्मत के साथ, जब इतनी बड़ी विपत्ति आती है चाहे घर में आए, राज्य में आए या देश में आए, उसे संभाला। एक व्यक्ति होता है जिसे जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आप सब लोगों ने उसे हिम्मत के साथ संभाला।

मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हिन्दुस्तान धार्मिक आस्थाओं का देश है। धार्मिक पर्यटन और आनंद के लिए पर्यटन में कोई न कोई अंतर बनाने की नीति जरूर होनी चाहिए। हमारे धार्मिक स्थल पर्यटन का केन्द्र बनते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोडेड होते जा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी जो मान्यताएं थीं या जो सिद्धान्त होने चाहिए, वहां उनका पालन नहीं होता। इसकी मौनीटरिंग के लिए वैष्णो देवी, अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड उदाहरण हैं। हर धार्मिक स्थल पर एक योजनाबद्ध तरीका होना चाहिए।

दूसरा, जो लोग गायब हुए हैं, उनका सात साल वाले कानून का मामला न हो। उसके लिए लॉ में चाहे कुछ भी अमैंडमैंट करना पड़े, सरकार के स्पैशल इफैक्ट से उन्हें जल्दी से जल्दी सर्टीफिकेट मिलना चाहिए कि they are deemed dead. तीसरा, मैं पेड़ों के विषय में कहना चाहूंगा। मान्यवर, आप वहां के ज्ञाता हैं, आपकी बात सुनने के बाद कुछ और कहने का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आपराधिक कृत्य किया गया है। किसी की भी सरकार रही हो, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। उत्तरांचल में पेड़ों का जिस तरह कटाव हुआ, वह आपराधिक है। उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे लिए इनवायर्नमैंटली जो पेड़ ठीक हैं, उन पेड़ों को लगाया जाए। गंगा ने हमें बर्बाद नहीं किया, बल्कि हम गंगा के रास्ते में आए। हमने बहुत सी चीजों का वॉयलेशन किया, जिसका हमें फल भुगतना पड़ रहा है।

मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बिजनौर की सीमा उत्तरांचल से शुरू होती है। मेरे क्षेत्र से 155 किलोमीटर लम्बी गंगा नदी होकर गुजरती है, लेकिन हम उसके लिए कोई नीति नहीं बना पाए। गंगा के आसपास कोई ऐसा कानून बने, जिससे लोग प्रभावित न हों। हर वर्ष सैंकड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लोग बर्बाद होते हैं। यह मेरा एक वेक-अप कॉल है, हमें खतरे की घंटी सुनाई दी है। इसके आधार पर आज यह बहस हुई है। यह बहुत गंभीर बहस है। लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इसलिए यह सिर्फ बहस होकर समाप्त न हो जाए, बल्कि इस पर विचार करके हिमालय के पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, जो हमारे मुकुट हैं, उनके लिए एक पूरी नीति बनाई जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि गंगा मैया सब पर कृपा रखे। हमारे ये राज्य फिर से फले-फूलें और इनमें लोगों का आना-जाना उसी तरह शुरू हो।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I express my profound sorrow and pay tribute to the persons who lost their lives due to the unprecedented catastrophe which occurred in Uttarakhand.

Sir, you might be remembering that in this House itself, we had discussions twice on pollution of the Ganga and the situation of the Himalayas. But I do not understand what sense of the House has been taken by the Government. It seems no sense has been taken up and only discussions took place for the sake of discussion.

I am not going to narrate the catastrophe. It has already been mentioned by several Members and it has been coming out in media also. But if we go through the chronology of events, the catastrophe occurred with the combination of massive rainfall, glaciers flow, snow melt, debris and thousands of land slides.

I listened to your speech very attentively as you are coming from that area which has been affected the most. You very rightly mentioned about the global warming. So far as global warming is concerned, what would be our task? Our task is not to create more problems. The opinion of the experts is that the reservoirs and tunnels built for the dams contribute in increasing the localised temperature, disturbing the ecological balance. It is pertinent to mention that due to the proximity of the Himalayas, this can be of immense danger. Cloudbursts are reported increasingly after the construction of Tehri and other projects in recent years. The Government should take this point into account.

I am just going to mention some points. The Char Dham Yatra is the main economic source of thousands of families in the hills, but no yatra plan or management plan was ever initiated and implemented by the Uttarakhand Government. ...(*Interruptions*) So, there should be a plan. But so far there is no plan.

The second point is, highways, hotels and massive building construction near the river banks caused a great loss too.

The third point is, the main reason behind the catastrophe is commercial exploitation of the Himalayas in the name of bumper to bumper developmental hydro projects. More than 500 sites have been identified for hydro power projects in the Ganga basin. Out of this, 70 projects are in pipeline in the main Ganga-Bhagirathi and her tributary Alaknanda and Mandakini.

The existing and the under-construction projects have severely affected the entire vicinity. Loss of grazing lands, dried water sources, disrupted flora, fauna and wild life due to uncontrolled heavy blasting for tunnelling, road building and power houses are seen besides massive de-forestation and unchecked dumping of muck in the river bed at all construction sites. This causes landslides and land sinking in monsoons and unstable the entire area.

So, what is meaning of development? In case of development, all these points should be taken into consideration. In the name of development, everything cannot be done. Not even a single village in the vicinity of the already existing projects can be termed as developed. So, these are the points.

So, my first suggestion is, implement the eco-zone notification keeping in mind the rights and privileges of local people; and further construction of roads and buildings should be carried out under proper master plan and guidelines of eco zone.

My second suggestion is, 150 kms. of the valley from the glacier line all across Himalayas must be declared and framed as Cultural Eco Sensitive Zone to maintain the original pristine state of the area.

My third suggestion is, scrap all the under construction dams, tunnelling, barrage and reservoir formation in Himalayas.

So, all these points should be taken into consideration.

I have two more questions to ask about the mismanagement of the Disaster Management Authority. ...(*Interruptions*) There is no correct figure about the rain fall, landslides, etc. What is the role of the Central Water Commission? What was the forecast of Meteorological Survey of India? So, all these things should be taken into consideration. So, these are my suggestions.

My last suggestion is that, we should not have discussions just for discussion sake. We should think of something for the coming days. Please constitute a High Power Committee from the Centre to monitor everything. That cannot left only to the State Government. Or, this is not the case of a particular Department or Ministry. Please constitute a High-Powered Committee. If you involve the Members of Parliament from both the Houses, it will be better. If it is not possible, it should be constituted involving experts. That should really be a High-Powered Committee to monitor everything above the developmental works, relief works and all these things....(*Interruptions*)

Lastly, Sir, I would just respond to your last sentence:

Sarve bhavantu sukhinah,

Sarve santu niramayah,

Sarve bhadrani pashyantu,

Ma kashcit duhkha bhagbhavet.

Only good wishes will not do. You have to do something. If you have to do something, you should be honest, you should be sincere to the cause. Otherwise, everything will be a futile exercise...(*Interruptions*) It will be a great loss. So, this is my suggestion.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, आपने मुझे उत्तराखण्ड की पीड़ा के साथ अपने को जोड़ने का मौका दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, पूरे सदन का एक स्वर है, चाहे यह पीड़ा भले ही उत्तराखण्ड की हो, लेकिन अभिव्यक्ति में इस देश के जिस किसी भी सांसद ने जो अपनी बातें कही, उसमें कहीं अंतर नहीं आया। ऐसे ही मौके पर हम सबों को याद आता है कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। यह पीड़ा उत्तराखण्ड की है। इस पीड़ा का कारण गंगा के कैचमेंट इलाके में है, जो हिमालय का उत्तराखण्ड है, उसमें एक भयानक वर्षा - अनप्रिसिडेंटेड रेन के चलते, शायद उत्तराखण्ड के इतिहास में इसकी कभी कल्पना नहीं की गयी थी, इससे भयानक बारिश, इससे भयानक त्रासदी कभी नहीं आयी होगी। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि उससे कितनी बड़ी दुर्घटना घटी, उससे कितने लोग मारे गये, कितनी परेशानियां आयीं। लेकिन मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, जिस वर्षा के साथ यह त्रासदी आयी, उसे कोई रोक नहीं सकता था। जब आसमान से बादल फटते हैं, तो कोई भी विज्ञान उस आसमान के बारिश को,फटे हुए बादल के पानी को रोक नहीं सकता है। जब 400 प्रतिशत बारिश एक सीमित समय में होगी, तो जो दुर्घटना घटी है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें सड़कें बह गयीं, घर बह गये, वर्षों से पैदा किये गये सारे विकास के साधन बह गये। उसके ये नतीजे होने थे। लेकिन जब आज हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा का मुख्य विषय 70-75 दिनों के बाद एक होना चाहिए कि उस उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए? जब मैं यह सुनता हूं कि उत्तराखण्ड की सरकार पंगु बन गयी थी, कोई कार्य नहीं कर सकी। मैं बिहार से संबंध रखता हूं। मैंने वर्षों तक पानी और बाढ़ को देखा है। मैं जानता हूं, जिस इलाके में पानी आता है, वहां का स्थानीय प्रशासन बिल्कुल पंगु हो जाता है क्योंकि वह भी आम नागरिकों के साथ पानी में घिर जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी गये, भारत की जो हमारी संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, वे उत्तराखण्ड को सही रूप से सहयोग नहीं कर पायीं। लेकिन फिर मैं दूसरी बात सुनता हूं कि वायुसेना की तारीफ हुई,

थल सेना की तारीफ हुई, ये भारत और केन्द्रीय सरकार की संस्थाएं हैं। आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों ने वहां पर जाकर जो सहयोग किया, वह भारत सरकार के निर्देश पर ही हुआ। महोदय, यदि देश नहीं दौड़ा होता, यदि सभी लोग सहयोग नहीं किये होते, तो उत्तराखण्ड का, जिसका खण्ड-खण्ड विखंडित हो चुका था, रास्ते बंद हो चुके थे, आवागमन के कोई साधन नहीं थे, कोई पहाड़ पर फंसा था, कोई नदियों के किनारे अपने जीवन को बचा रहा था, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि जब कोसी की त्रासदी आयी थी, तो उसे हम सभी ने झेला था और हम लोगों ने देखा था, यदि पूरा देश नहीं दौड़ा होता, तो बिहार में कोसी की त्रासदी के बाद बिहार को कोई नहीं बचा पाता।

महोदय, जिस तरह से कोसी की त्रासदी के बाद पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए, उसी तरह से अब सारी बहस का केन्द्र एक होना चाहिए कि उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण कैसे हो? हमारे चारों धाम वहीं पर हैं। हमारे पर्यटक वहां जाएंगे। उनके लिए जो जो भी सुविधाएं थीं, वे सब नष्ट हो चुकी हैं। बात उसके आगे बढ़ने की है। जितने विकास के बिन्दु खड़े किए गए हैं उत्तराखण्ड में, जब मैं सुनता हूं कि वे कारण हैं इस विनाश का, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। उत्तराखण्ड के पास जल, जंगल और हमारी देवभूमि के रूप में आस्था के केन्द्र हैं। ये ही उत्तराखण्ड की पूंजी हैं। हम जिस दिन जल के प्रबंधन को रोक देंगे, जिस दिन हिमालय के पहाड़ों पर जल का प्रबंधन रुक जाएगा और हमारे जितने विकास के बिन्दु खड़े होते हैं, उनको रोक डालेंगे, तो न ही उत्तराखण्ड, न ही हिमाचल प्रदेश, आप सिक्किम, भूटान और अरूणाचल प्रदेश तक चले जाइए, कोई वहां बच नहीं सकता है, वहां के जीवन का आधार यही है। यदि टिहरी डैम नहीं हुआ होता, सचमुच ही पता चल गया होता कि उत्तराखण्ड का यह पानी किस तरह से इस देश के सभी हिस्सों में नुकसान कर देता। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल निचले हिस्से हैं, लेकिन एक अकेले टिहरी के जलाशय ने, अलकनंदा और मंदाकिनी के पानी छोड़कर भिलांगना, धौलीगंगा, भागीरथी के पानी को टिहरी में जो एक बड़ा जलाशय बना है, उसने सारे पानी को एब्जार्ब कर लिया। यदि वह पानी निकला होता, उस पानी के साथ रुद्रप्रयाग के बाद, जहां से गंगा का असली स्वरूप निकलता है, तो पता चल गया होता कि नीचे के इलाकों में कितना नुकसान हो सकता है। इस बहस को वहां केंद्रित न किया जाए कि उत्तराखण्ड का गलत विकास के कारण वर्तमान में नुकसान हुआ है। वहां विकास के सारे कार्यों को पर्यावरण और जंगल के नाम पर हम उत्तराखण्ड को विकास के रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत मर्यादित ढंग से हम जब कष्ट और पीड़ा में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो हम उत्तराखण्ड के भविष्य को खतरे में न डाल दें क्योंकि जल ही वहां की सबसे बड़ी पूंजी है। जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट हों, यदि वहां उसकी निकासी बंद हो जाए, उसी तरह जल के प्रबंधन को रोक दिया जाए, तो उत्तराखण्ड का भविष्य में बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का उचित प्रबंधन हो क्योंकि बादल फटेंगे तो सड़कें टूटेंगी, लेकिन पुनर्निर्माण देश के लोगों को मिलकर करना है। जिस स्वर में हम लोगों ने एक बात यहां कही है, उसी तरह से एकजुट होकर उत्तराखण्ड का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है, अन्य बातों से हम कहीं उत्तराखण्ड का नुकसान न कर दें।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to take part in this discussion under Rule 193 on the tragedy that occurred in Uttarakhand. It is fortuitous that you are in the Chair and you were the man on the spot but let me also at this point thank the Uttarakhand Government and the Government of India that several families from Sikkim were rescued in time. I would like to place on record the gratitude to the Government of Uttarakhand and the Government of India from our State.

This morning, it was very apparent in the discussions that ensued in `Zero Hour' that many MPs from Bihar made their representations with respect to either drought or flood or both droughts and floods that are happening in their States. It is with regularity every year that we hear this. Every year, we hear of one big tragedy. In 2011, on September 18, we had a massive earthquake in Sikkim. Even as recent as two days ago, several families in West Sikkim were washed away because of landslides. This kind of regularity of natural disasters, as we would like to call them, is happening on an absolute regular basis. Therefore, that brings us to the question as to how prepared are we in dealing with these kinds of natural disasters.

I recall that when Tsunami happened, the Government of India made a provision and quickly put up early warning systems for the Tsunami. Now this is something which, I hope and pray, will give us early warning if there were to be a tsunami. But what is important to understand is that the entire Himalayan belt is a seismic zone, it is a very fragile mountain system and, with climate change, the precipitation of rain is going to become increasingly more vociferous, and, therefore, I think, early warning systems, as you have rightly said, should be immediately put up all across the Himalayas so that any part of the Himalayas which is susceptible to disaster gets early warning.

The other thing which I would like to reiterate, and which the hon. Member Shri Sharad Yadav said today, is that we need to have a new Ministry, a Ministry that looks after the mountains. These geographical formations, be it a desert area, be it coastal areas, are today recognised as biodiversity hot spots and, therefore, we need to see as to how we can deal with environmental disasters or environmental development that needs to take place.

Finally, I would just like to make one more point and this is with regard to the NDRF. I think much has been said with respect to the kind of work and the kind of valour that our people from the Armed Forces have shown. I can tell you that we did not have to import the kind of forces for rescue and rehabilitation because in the State of Sikkim, what we have done is, we have taken disaster management to the grassroots and each panchayat is being equipped with disaster management techniques. I think that is the way forward. It is not that by sitting at the Centre that we need to do this kind of disaster management training. Capacity building has to be done at the grassroots, at the level of panchayats. I think our State has shown the way forward.

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): माननीय सभापति जी, उत्तराखण्ड में, खासकर केदारनाथ क्षेत्र में पिछली 16-17 जून को जो प्राकृतिक आपदा आई, मैं उसकी ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं और अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहती हूं। उत्तराखण्ड के टिहरी इलाके में उत्तरकाशी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग में जो प्राकृतिक आपदा आई वह कल्पना से परे है। मैं 18 तारीख से करीब एक महीने तक उत्तरकाशी एरिया में थी इसलिए मुझे उसका अनुभव है। आज इस विषय पर चर्चा हो रही है और कई बातों को यहां कहा गया है, मुझे काफी अच्छा लगा। करीब हर राज्य के सदस्यों ने यहां पर उस विभीषिका के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूं।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर हमारी डिफेंस के लोग नहीं होते तो हमारे उत्तराखण्ड के लोग और देश के विभिन्न भागों से आए हुए इतने लोग भी नहीं बच सकते थे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखण्ड सरकार का जो सहयोग होना चाहिए था, वह वहां के निवासियों को नहीं मिला। यह फैक्ट है, क्योंकि मैं एक महीने तक जहां यह आपदा आई थी, उत्तरकाशी के लोगों के बीच रही थी। वहां मैंने देखा और जो मुझे अनुभव हुआ, वह मैं यहां बताना चाहती हूं।

उत्तरकाशी, जो हिमालय क्षेत्र है, वहां की हालत बहुत ही खराब है। खासकर उत्तरकाशी में हर गांव को आप देखें तो वहां की हालत बहुत खराब है, रास्ते बहुत खराब हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोकल लोग हैं, उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई है। जो खाद्यान्न वहां गया वह अच्छी तरह से बांटा नहीं गया। मैं वहां थी और जानती हूं कि वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? शुरु में जो काम वहां होने चाहिए थे वे नहीं हुए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 19 तारीख को जब मैंने सब देखा और चूंकि मैं डिफेंस कमेटी में हूं तो मैंने डिफेंस कमेटी के लोगों को फोन करवाया और बोला कि हमें एयर-फोर्स के प्लेन चाहिए क्योंकि छोटे हैलीकोप्टर में केवल दो-तीन आदमी ही जा सकते हैं और उनसे काम नहीं चल रहा था। उनके आने के बाद लोगों की बहुत सहायता हुई। जैसा कि आपने बोला कि डिफेंस की जरूरत सिक्किम में नहीं पड़ती है, मैं उसे समझती हूं लेकिन हमारे वहां वह सिस्टम नहीं है। हमारे को बचाने वाले डिफेंस वाले, लोकल लोग और पुलिस के जवान ही थे। जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों को, लोकल लोगों को और टूरिस्ट्स को बचाया है मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जहां डिफेंस के लोग रुके थे मैं भी वहीं रुकी थी। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूं। त्रासदी की जगह के अनुभव में और ऑफिस में बैठने के अनुभव में अंतर होता है, इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि डिफेंस के लोग सुबह 6 बजे हैलीकोप्टर लेकर जाते थे और उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की और जो लोग वहां थे वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का रिस्क लिया। एक हैलीकोप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जो उसके कैप्टेन और कमांडर थे मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से पहले से ही जानती थी और हम लोग साथ थे। मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि हरसिल और गंगोत्री में मैं गयी थी और गंगोत्री में मैं सबसे पहले गयी थी। वहां की हालत बहुत खराब थी। हरसिल में जिस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था मैं उसमें आने वाली थी, किसी कारण मैं उसमें नहीं आ सकी और बच गयी। मैं डिफेंस को लोगों को सबसे ज्यादा सैल्यूट करना चाहती हूं जिन्होंने हमारे लोगों को बचाया। आज उत्तरकाशी की हालत बहुत खराब है लेकिन सरकार अगर पहले से ही सजग होती तो ऐसा नहीं होता। आपदा वर्ष 2012 में भी आई थी और उस समय जो पैसा दिया गया था अगर उसका अच्छी तरह से उपयोग किया गया होता तो आज उत्तरकाशी का यह हाल नहीं होता। उत्तरकाशी चिन्यालिसोर के गांव में कनैक्टिविटी नहीं रह गयी है। वहां गांव में 46 महिलाएं प्रैग्नेंट हैं जिनकी डिलीवरी इसी महीने होने वाली है लेकिन वहां कनैक्टिविटी नहीं है और उनकी सहायता कैसे होगी? मैं अभी वहां गयी थी और जो पैसा उन लोगों को मिलना था वह भी थोड़ा-थोड़ा ही मिला है। आप यकीन नहीं करेंगे ऐसे गांव भी थे जहां पटवारी लोग लैंड के लिए केवल 255 रुपये दे रहे थे जबकि 255 रुपया तो टैक्सी का किराया भी नहीं होता है। मैंने तो खुद बोला कि 255 रुपये लेकर आप क्या करोगे? इतनी बेइंसाफी होनी नहीं चाहिए। मैं वहां जो हो रहा है वही आपको बता रही हूं क्योंकि जिसे वहां का अनुभव है वही वहां के फैक्ट्स के बारे में बता सकता है। मेरी माननीय प्रधान मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें बताया कि वहां फंड नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो वे कहते हैं कि पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतना पैसा वहां भेजा है। आपने पैसा भेजा होगा मगर गया कहां? पैसा आया है और हरेक जगह से आया है it has not been given to the proper people, I do not know where the money is. मैं यह जानना चाहती हूं कि जो पैसा गया और जो हमारे एमपीज लोगों ने भी डोनेट किया, वह पैसा गया कहां? हमारे टिहरी के लोगों को तो वह पैसा मिला नहीं, वह पैसा गया कहां, यह मैं जानना चाहती हूं। उन लोगों को जो खाना दिया गया है, आप यकीन नहीं करेंगे जो लोग चल नहीं पाते थे, उनके कंधों पर खाना लेकर जाते थे। वहां आटे की जगह गेहूं दिया गया है और उनके पास गेहूं पीसने के लिए चक्की नहीं है। नमक भी नहीं दिया गया। वहां खाना खराब हो रहा था, लेकिन बंटवाया नहीं जा रहा था। हरसिल में गरीब लोग अपने घर से खाने का सामान बंटवा रहे थे। मैंने कहा कि जो खाना सड़ रहा है, उसे लोगों में बंटवा दिया जाए लेकिन सही मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब ऐसा डिजास्टर होता है, तो यह भेदभाव नहीं करना चाहिए यहां यह सरकार है या कोई दूसरी सरकार है। यह मानवीयता की बात है।

आज मेरी पहली स्पीच है। मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूं, I hope you don't mind. मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सिर्फ आफिस में बैठ कर करना और स्पॉट पर काम करना, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जैसा श्री राव ने कहा, उनमें बहुत फीलिंग आई क्योंकि वे भी वहीं पर थे और मैं भी स्पॉट पर थी। मैं सांसद की हैसीयत से बोलना चाहती हूं कि हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारा जो टिहरी गढ़वाल है, यहां हमने सब कुछ खो दिया है लेकिन हमारे लोगों को अभी तक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। सभापति जी, आप तो जानते हैं कि विस्थापित लोगों को अभी तक घर नहीं मिला है। प्रताप नगर में आज तक डोबराचाटी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। यह बहुत छोटा पुल है। मुम्बई में बहुत बड़ा पुल बना है और हमारे यहां इतना छोटा पुल क्यों नहीं बन सकता है? यह बहुत दुख की बात है कि पुल बनाने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है। जैसा हमें ट्रीट किया जा रहा है, यह बहुत दुख की बात है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे लोगों की तरफ देखा जाए। जब यह डिजास्टर हुआ था, तब सभी लोगों का ध्यान पर्यटकों पर था, लेकिन लोकल लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वहां के लोकल लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। वे तो अपने टूटे घरों में भी नहीं जा सकते हैं। आप उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दें। उन लोगों को पूरा मुआवजा देना चाहिए। उनके लोन माफ कर देने चाहिए। आप जानते हैं कि पहाड़ों में जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। ऐसे समय में यह नहीं देखना चाहिए कि बीपीएल से संबंधित है या एपीएल का है। सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, अगर उनका सब कुछ लुट गया है, तो सभी को एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे वहां जो स्कूल हैं या अस्पताल हैं वहां कोई बंदोबस्त नहीं है। वहां अस्पताल में प्रोपर डाक्टर और मशीनरी नहीं है। किसी-किसी अस्पताल में तो ब्लड टैस्ट की जगह भी नहीं है। एक्सरे वगैरह के लिए कोई इक्वीपमेंट्स भी नहीं हैं। सिर्फ टिहरी गढ़वाल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड में जहां-जहां भी डिजास्टर हुआ है, सभी के लिए मैं मांग करना चाहती हूं कि they should be treated well and they should be given whatever they need. मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो फंड वहां गया है, it has not been distributed. आप भी गये हैं लेकिन मैं यह बोलना चाहती हूं कि It should be fair and it should be distributed. It should be given to everyone who needs it. उनको भी देना चाहिए जिन्होंने अपने घर से सब चीजें निकालकर दूसरों की मदद की। They should also be treated equally.

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सर्वप्रथम यूपीए सरकार के प्रधान मंत्री जी

को और यूपीए चेयरपर्सन को, पक्ष को, प्रतिपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में सब उत्तराखंड के साथ खड़े हुए हैं। आज भी सभी माननीय सदस्यों ने उत्तराखंड के प्रति अपना दर्द व्यक्त किया। इस बार जो उत्तराखंड में त्रासदी आई, यह अभूतपूर्व थी। इसने उत्तराखंड के किसी कोने को नहीं छोड़ा। एक तरफ हमारा उत्तरकाशी का जिला हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ है और दूसरी ओर मेरा जो लोक सभा क्षेत्र का पिथौरागढ़ जिला है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा को छूता है, वहां तक यह पूरी त्रासदी एक साथ आई है क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में इस समय यात्रा का सीजन था। हजारों तीर्थयात्री इसमें फंस चुके थे। इसलिए पूरे देश का ध्यान उस त्रासदी की ओर गया जिसमें बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजडी भी हुई। यह इसी साल की बात है। मेरा पांचवा साल चल रहा है और हर बरसात में, जब बारिश होती है यानि जून-जुलाई-सितम्बर तक दिल डरता रहता है क्योंकि यह आज की बात नहीं है। वर्ष 2009 में मेरे ही क्षेत्र में बादल फटने से मुन्स्यारी में 40 लोगों की मौत हुई। उसके बाद अगले साल 2010 में सूमगढ़-बागेश्वर में एक स्कूल में दबकर मासूम बच्चे शहीद हो गये। वहां भी बादल फटा था। 2011 में अल्मोड़ा जिले के अंदर 3-4 गांव वॉश-आउट हो गये। कई लोगों की मौत हुई। पिछली बार मेरे ही संसदीय क्षेत्र के बागेश्वर के कपकोट में पोथिंग में एक गांव है, वहां भी त्रासदी हुई। वहां बादल फटा और वहां ह्यूमन कैजुअल्टी हुई। इस साल धारचूला-मुन्स्यारी पूरी तरह से शेष दुनिया से कट गया।

आज पूरे उत्तराखंड की यही स्थिति है। हम सभी का ध्यान हजारों तीर्थयात्री जो दूर अंचलों से वहां आए थे क्योंकि पीक सीजन था और इस बार जो बरसात आई, वैसे भी देश के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा भी था कि मानसून 10-15 दिन पहले आया और शुरुआती बारिश ने ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहर बरपाया। राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो संभव सहायता थी, वह करने की कोशिश की। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई, यह इतनी बड़ी त्रासदी थी कि वहां की सरकार और भारत सरकार ने जो संभव था, वह किया और मैं नहीं समझता हूं कि ये सब उतनी बड़ी त्रासदी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयार थे। लेकिन अपने संदर्भ में राज्य सरकार ने तमाम कोशिशें कीं। सवाल है कि यह त्रासदी हर साल क्यों आ रही है? हर साल कभी बादल फट रहे हैं, कभी लैंड-स्लाइड हो रहा है, कभी वहां पर अर्थक्वैक आ रहे हैं। पिछले 8-10 सालों से यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। यह सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? हम इस सारे सिलसिले को प्राकृतिक आपदा कहकर नहीं बच सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदा के साथ इसमें कुछ न कुछ ह्यूमन कंटेंट भी है।

यह मानव निर्मित प्राकृतिक आपदा है। इन दोनों का कहीं न कहीं संबंध है। इसको भी समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हो रहा है? इस बार जितनी नदियां आई, चाहे गंगा थी, चाहे अलकनंदा थी और मेरे क्षेत्र में कालीधौली नदियां थीं। वे नदियां जो जीवनदायिनी थीं, वे इस बार मौत के दानव के साथ आई थीं। उनमें इतना पानी बहा लेकिन उनमें जो रेत है, जो डस्ट है, जो मड है, वह आखिर कहां से आया? तबाही का कारण वह क्यों बना? वो कौन सी ऐसी नीतियां हैं? उनके संदर्भ में भी हम सबको सोचना पड़ेगा। सब कह रहे हैं कि हिमालय बहुत ही सेंसिटिव ज़ोन है। फ्रेजाइल ज़ोन है। यह हिमालय अर्थक्वैक के हिसाब से ज़ोन-5 में आता है। क्या उस संदर्भ में हमको अपनी नीतियां बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? सड़कों की जो तकनीक पुरानी है उस पर नए सिरे से विचार की आवश्यकता है। आज पूरे उत्तराखंड में इस त्रासदी के बाद जब सारे लोगों को हमने रैस्क्यू कर लिया है तो हमारे सामने सबसे बड़ा विकल्प है कि हमारी उन कनैक्टिविटी को जोड़ सकें? मेरे क्षेत्र में धारचुला से ले कर, मैं स्वयं 18 तारीख को वहां पर पहुंचा, यह क्षेत्र कैलाश मानसरोवर, तिब्बत और नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। सबसे पहला पॉइंट था जॉलजीबी। जॉलजीबी से ले कर धारचुला तक, लगभग 20-30 किलोमीटर की यात्रा या तो मैंने पैदल की या बीच-बीच में जीप से यात्रा की। सबसे पहले जॉलजीबी में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पैदल पुल, जो ऐतिहासिक पुल है, वहां पर हर साल मेला लगता है, वह पुल वाशआउट हो गया। उसके बाद बलवाकोट है, 20-25 दुकानें, जिस तरह से आपने बहुत से टीवी दृश्यों में उत्तरकाशी की दुकानें देखी होंगी कि कैसे वे एक साथ नदी में वाशआउट हो गई। लोगों के बड़े-बड़े घर नदी में वाशआउट हो गए। इतने गांव, बलवापुर से आगे गोठी, नईबस्ती, न्यू सोवला, घट्टाबगड़ आदि के सब लोग हमसे कह रहे थे कि वे टेंटों में रह रहे हैं कि अब हम दो-तीन महीने बाद जाएंगे। कहां जाएंगे? वह पूरा का पूरा गांव वाशआउट हो चुका है, सोबला-डार के पास। वहां सरकार को टेंट लगाने के लिए जमीन नहीं मिली। जब मैं धारचुला में गया और देखा कि वहां पर टेंट नहीं लगे थे। मैंने सोचा कि लोगों ने प्रशासन को शिकायत की क्योंकि हैलिकॉप्टर के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। चार मोटरब्रिज वहां पर वाशआउट हो चुके थे। हैलिकॉप्टर्स में बड़े-बड़े टेंट नहीं जा सकते है। मैं खुद वहां पर गया तो देखा कि वहां कहां टेंट लगाएंगे? आज वे जीआईसी धारचुला में रह रहे हैं। मैं और आपदा मंत्री वहां पर थे। उन्होंने कहा कि तीन महीने बाद, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जिस इंटर कॉलेज में, जहां आज हम रह रहे है, यहां के बच्चे कहेंगे कि हमारी कक्षाएं कहां चलेंगी तो उस दिन हम कहां जाएंगे।

घट्टाबगड़ में, वहां पर जो अधिकांश कमज़ोर वर्ग के लोग थे, आज जंगलात की जमीनों पर अस्थायी रूप से टैण्टों में रह रहे हैं। उनके सामने भी यह समस्या है कि दो-तीन महीने बाद, बरसात के बाद फिर वे कहां जाएंगे। राज्य सरकार ने भी पुनर्वास के लिए, रीहैबिलटेशन के लिए एक प्लान भेजा, आपसे अनुरोध भी किया है, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि इस समय उत्तराखण्ड के अंदर 290-292 गांवों को राज्य सरकार ने आईडेंटीफाइ किया था, कुछ गांव, उनकी संख्या 300 से ऊपर है, इनको री-एलोकेट करना ही करना है। सवाल है कि इन गांवों को कहां री-ऐलोकेट करना है इसमें दो तरह के गांव हैं। एक तो जिनको हमने सेंसिटिव जोन कर दिया है। उनके लिए हमको एक दीर्घकालीन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कुछ गांव हैं जहां के लोग इस वक्त भी टेंटों में रह रहे हैं, हमारी सरकार उनके लिए शेल्टर बना रही है, लेकिन वे उन शेल्टरों में कितने दिन रह पाएंगे? किसान और गांवों के लोगो को बसाने के लिए या तो उन्हें उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में ही बसाया जा सकता है या तराई के अंदर बसाया जा सकता है। लेकिन अगर उन्हीं पहाड़ियों में आप उनको बसाएंगे, तो वहां की ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी, वहां जंगल व जमीन कम है। पिथौरागढ़ जिले के अंदर लगभग 14 सौ परिवार है, उनको भी बसाने की समस्या है। उन 14 सौ परिवारों के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार को सोचना है। क्या हम उनको एक एकड़ जमीन देंगे? किसान को अगर खेती की जमीन नहीं मिलेगी, वह किसी भी घर में दूसरी जगह नहीं जाएगा। इस विषय में राज्य सरकार ने 8 हज़ार करोड़ रूपये का रीसैटलमेंट और रीहैबिलटेशन का जो प्रस्ताव बनाया है, उसके संदर्भ में आपका अधिकतम सहयोग, केंद्र सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी का और सब का सहयोग मिलेगा। उन गांवों के लिए हमको एक मुकम्मल नीति तो बनानी ही पड़ेगी। मेरा कहना है कि तराई के अंदर जो हमारी तराई है, उधम सिंह नगर की तराई में, हमने बहुत लंबे समय से, तरह-तरह से लोगों को जमीन दी है। वहां पर इंडस्ट्री के लिए जगह दी है, हमने वहां पर लोगों को रियल-एस्टेट के लिए जगह दी है। हमने वहां पर दूसरे राज्यों से शरणार्थी बने लोगों के लिए जगह दी है। उत्तराखण्ड के जो दूरस्थ इलाकों के लोग थे, जो उजड़ गए, सोबला-डार के लोग उजड़ गए, जो पूरा गांव वाशआउट हो गया, उनके लिए कहीं कुछ जगह नहीं बची है। वे लोग भी कह रहे हैं कि क्या हमारे लिए भी एक एकड़ जमीन वहां मिलेगी या नहीं मिलेगी? भारत सरकार के सहयोग से ही राज्य सरकार यह कर सकती है। सन् 1977 में जब मैं विद्यार्थी था, हमारे उसी तवाघाट में लैण्डस्लाइड आया था। एक पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। उसमें 30-40 लोग मरे थे। बाद में राज्य सरकार ने तय किया कि इस गांव को नई जगह बसाना होगा। वह सितारगंज उधम सिंह नगर में बसाया गया। एक-एक एकड़ जमीन दी गई। आज वे लोग अमन चैन से रह रहे है।

सभापति जी, मैं आपके मध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आज वहां पर सबसे बड़ी समस्या कनैक्टिविटी की है। तवाघाट से ले कर गूंजी तक, पूरी की पूरी रोड़ को ठीक करने में लगभग 6 महीने से ऊपर का समय लगेगा।

21.00 hrs.

धारचुला से तवाघाट तक छोटी जीपें जा रही हैं, लेकिन तवाघाट से आगे, ऊपर का जो हमारा क्षेत्र है, जो धारचुला का ऊपर का क्षेत्र है, जहां हमारे ट्राइबल लोग 6 महीने जाते हैं और 6 महीने माइग्रेट करके नीचे आ जाते हैं। उसी तरह से मुन्स्यारी तहसील के ऊपर जोहार का क्षेत्र है, जहां हमारे लोग 6 महीने जाते हैं, उनकी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। उसके लिए हमने बीआरओ से बात की, हमारे जिला प्रशासन ने भी बात की, अगर वह कनेक्टिविटी जोड़नी है तो भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय की जरूरत है। उन रोड्स को ठीक करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से सपोर्ट की जरूरत है और वहां के बीआरओ ने इसके लिए डिफेंस मंत्रालय को लिखा भी है। अगर इसके लिए भारत सरकार का सहयोग मिल जायेगा तो उसके संदर्भ में मैं समझता हूं कि वह कनेक्टिविटी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जायेगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन महोदय मैं आपके माध्यम से अंत में एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि हिमालय को हिमालय की नजरों से देखना पड़ेगा। हिमालय को हमको शेष देश की जरूरतों के हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा, हिमालय को हिमालय की नजरों से देखना पड़ेगा और उसी आधार पर प्लानिंग कमीशन ने एक टास्क फोर्स बनायी थी। बी.जी. मुखर्जी जो भारत सरकार के ट्राइबल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट के पास आज भी वह पड़ी है, वह रिपोर्ट मेरे पास भी है।

महोदय, वर्ष 1982 में स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिलाया था कि हिमालय के लिए हमको हिमालय की नीति बनानी चाहिए। एस.जेड.कासिम जी के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था कि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए या तो हिमालय डेवलपमेंट अथॉरिटी बना लीजिए। हिमालय के विकास के लिए एक नयी सोच की जरूरत है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, वे जीवनदायिनी हैं, उनका रूप बिगाड़ा है। हम वहां जो रोड्स बना रहे हैं, जिस डायनामाइट का हम वहां उपयोग कर रहे हैं, वह डायनामाइट पहाड़ के फ्रेजाइल को तोड़ रहा है। यह जो मिट्टी, मग वहां पर आया, आज तवाघाट से पहले जो एनएचपीसी का पावर प्रोजेक्ट है, 280 मेगावाट का जो अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट था, इस बरसात में वह पावर प्रोजेक्ट बंद हो गया। पावर प्रोजेक्ट बहा नहीं, वह वहीं का वहीं है, लेकिन ऊपर से डांग से टनल के माध्यम से जो पानी आया, जो मिट्टी आयी, जो गाद आयी तो वह 280 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट समाप्त हो गया। आज हमको हिमालय के अन्दर इस बात को देखना होगा कि जो हिमालय के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हम बड़े डैम नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो टनल बना रहे हैं, उन टनलों में जो विस्फोट हो रहे हैं, वे पहाड़ को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए बड़े डैमों के बाद रन- ऑफ-दी-रीवर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में हमें नये सिरे से सोचना पड़ेगा। यह कमेटी की रिपोर्ट ने भी कहा है कि भारत सरकार को एन्टायर हिमालय जोन में जो सेन्सिटिव जोन हैं, उस क्षेत्र में इस तरह की चीजों को, विकास के मॉडल पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। वहां की रोड्स की तकनीक, जो आज दुनिया में रोड्स बन रही हैं, यूरोप के अन्दर रोड बन रही है, अमेरिका के अन्दर रोड बन रही है, चाइना हमारे पास तक लेकर आ चुका है, वहां पर लैंड स्लाइड का खतरा क्यों नहीं आया? वहां ऑल वेदर रोड्स बननी चाहिए।

अंत में मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमारी बहुत सी कनेक्टिविटी की सड़कें हैं, कुछ सड़कें डिफेंस के द्वारा बनायी जा रही हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा बनायी जा रही हैं, लेकिन पिछले आठ-दस सालों से उन रोड्स की गति में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। मुन्स्यारी एक जोन है, 150 किलोमीटर का यह एरिया है, यह कनेक्टिविटी से दूर है, यहां की 60 किलोमीटर की सड़क पिछले दस सालों से बन रही थी, लेकिन वह अभी तक बन नहीं पायी है। उसकी गति को तेज करना पड़ेगा। सोबला-डार-बातिंग तक की हमारी सीमा तक की जो सड़क है, इस सड़क के निर्माण को और तेज करना पड़ेगा। तवाघाट-गुंजी की जो सड़क है, वह सड़क ऊपर से बन रही है, लोगों का कहना है कि अगर नीचे से भी उसका तेजी से विकास होगा तो लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। जो बरसात के समय इसमें लोग फंस जाते हैं, उसमें सुविधा होगी। जो हम सिर्फ हेलीकॉप्टर के ऊपर डिपेंड हैं, उसकी जगह इन सड़कों के माध्यम से भी हम आगे बढ़ पायेंगे। अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, चूंकि तीर्थयात्रा की बात आयी है, इस पूरी यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा तो साथ-साथ है ही, इस त्रासदी में हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बंद हो चुकी है। पूरे भारतवर्ष में कैलाश मानसरोवर यात्रा मेरे ही संसदीय क्षेत्र से, तवाघाट से होते हुए जाती है। इस समय इस त्रासदी में गुंजी से लेकर कैलाश तक वह यात्रा गई। तवाघाट से लेकर गुंजी तक पैदल सड़कों के माध्यम से जाते थे, लेकिन भारत सरकार ने वह यात्रा रोक दी है। मेरा भारत सरकार से और राज्य सरकार दोनों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में उसको रोका न जाए। वह हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत भी है। साथ ही साथ जब तक वहाँ पैदल रास्तों को ठीक न किया जा सके, तब तक पिथौरागढ़ से या धारचूला से, चूँकि गुंजी में हैलीपैड राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ है, पिथौरागढ़ में भी हमारी एयर स्ट्रिप है, धारचूला में भी है, वहाँ से उस यात्रा को हैलीकॉप्टर के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। उसके लिए अगर किसी प्रकार से यात्रियों को ट्रांसपोर्ट में सबसिडी दी जा सकती है तो कैलाश-मानसरोवर यात्रा शुरू की जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। मैं फिर एक बार भारत सरकार का और राज्य सरकार का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि इस कष्ट में हमारा साथ दिया।

* **SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM) :** I would like to express my views on the statement made by the Minister of Defence on 06.08.2013 regarding Government of India's response and measures taken for relief and reconstruction in the wake of natural disaster in Uttarakhand raised by Shrimati Sushma Swaraj on the 30th August, 2013.

The Uttarakhand tragedy is a man-made disaster of unforgivable magnitude, and not death and devastation caused by nature's fury. This unmitigated failure happened due to sand mining, stone quarrying forest cutting and construction mafias by bending or breaking about rules and regulations that strike at the ecological balance of a sensitive region. Uttarakhand Chief Minister, Vijay Bahuguna called the calamity a "Himalayan Tsunami".

The extensive death and destruction wreaked by the heavy rain, cloudbursts, flash floods and landslides in the hills of Himachal Pradesh and Uttarakhand foremost serve to remind man how small he is compared to the power of nature.

In this connection, I would like to commend up on the exemplary search rescue and relief operations carried out by the Army, Air Force, NDRF, ITBP and SSB in Uttarakhand and Himachal Pradesh.

What we witnessed in the Himalayas in June 2013 was nature's fury that was waiting to happen. Nature has been giving us enough indications which we choose to ignore. The Himalayan zone is ecologically very sensitive zone, while rampant construction in unscientific manner has made thing worse. It is high time we strictly regulate all such construction activities

to minimize damage to the hills.

---

*__श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):__ उत्तराखण्ड त्रासदी पर नियम 193 के अंतर्गत हो रही चर्चा पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस त्रासदी की भयंकरता, इसके कारण तथा परिणाम आपदा प्रबंधन की स्थिति, सेना तथा सुरक्षा बलों द्वारा राहत कार्यों में किए गए असाधारण साहसिक परिश्रम इत्यादि पर विस्तार से सदन को अवगत कराया है । इस प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप उत्तराखंड की वर्तमान दशा तथा उत्तराखण्ड के तुंत पुनर्निर्माण किए जाने के लिए अपेक्षित प्रयासों की भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है । इन सब विचारों के साथ स्वयं को संबद्ध करते हुए दो-तीन बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

पहली बात यह है कि इस त्रासदी के समय प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता अत्यंत पीड़ादायक तथा चिंताजनक थी । इस संवेदनहीनता के अनेक आयाम थे । उत्तराखण्ड की यह आपदा बहुत भयानक थी । किन्हीं भी कारणों से इसका समय से अनुमान लगाने में सरकार विफल रही, मैं उन कारणों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता परंतु 18-19 मई तक सरकार को इस आपदा की भयंकरता की जानकारी मिल गयी थी। पूरी केदारघाटी समाप्त हो गई थी, पुल टूट गए थे, सैकड़ों धर्मशालाएँ, होटल बह गए थे परंतु सरकार की संवेदनहीनता का हाल यह था कि पहले दिन से लेकर त्रासदी के एक-डेढ़ महीने बाद तक सरकार के मंत्री जनहानि को बहुत कम बताते रहे । उत्तराखण्ड के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जब दस हजार से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने का बयान दिया गया तो सरकार के संवेदनहीन मुखिया द्वारा इस बयान का तुंत खण्डन किया गया । मुख्यमंत्री महोदय बरामद किए गए शवों की संख्या को ही मारे गए व्यक्तियों की संख्या बताते रहे । अध्यक्षा जी मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा करके मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहते थे ? संवेदनहीनता का एक अन्य आयाम राहत कार्यों की व्यवस्था में दिखाई देता था । मुख्यमंत्री जी कहीं भी तथा कभी भी राहत कार्यों का समन्वय, निरीक्षण अथवा नियोजन करते नहीं दिखाई दिये । इसके विपरीत मुख्यमंत्री तथा उनकी सरकार डिजेस्टर टूरिज्म में व्यस्त थे, राहत सामग्री में अपने नेताओं के चित्र भेजने की योजना बनाने में लगे थे । संवेदनहीनता की यह स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी ।

राष्ट्रीय आपदा का यह चुनौतीपूर्ण क्षण राष्ट्रीय आह्वान का विषय बन सकता था । उत्तराखण्ड के ये तीर्थ संपूर्ण देश के हैं, सारे देश से तीर्थयात्री वहाँ आते हैं परंतु केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की क्षुद्र दृष्टि ने इस आपत्ति में सम्पूर्ण देश को एकजुट होकर खड़े करने का अवसर गँवा दिया । प्रत्येक राज्य से सहायता के लिए व्यक्ति गए परन्तु उनके प्रयासों का अपेक्षित सम्मान उत्तराखण्ड सरकार नहीं कर सकी ।

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र है । इसकी भौगोलिक दृष्टि से चिंता किया जाना आवश्यक है। प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ करने का यह प्रतिफल हमें मिला है, अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से इस संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है - मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता परंतु भविष्य के लिए इस त्रासदी से शिक्षा लिया जाना आवश्यक है ।

अन्त में उत्तराखण्ड त्रासदी में पीड़ित हुए परिवारों के प्रति संवेदना प्रगट करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): Mr. Chairman, Sir, I express my deep gratitude to all the distinguished Members, who have actively participated in the meaningful discussion on Uttarakhand disaster. ...(*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): रिप्लाई तो कल के लिए बोला था। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रिप्लाई अभी है। कल के लिए नहीं बोला था।

...(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Shrimati Sushma Swaraj has initiated the discussion and she has immensely contributed to this debate. Her speech was insightful. She has given a graphic picture about the Uttarakhand disaster as also the aftermath of the disaster. I specially thank her for her valuable suggestions and observations.

Sir, this august House has benefited greatly from the observations made by the hon. Chairman, Shri Satpal Maharaj as also Raje Lakshmi ji and Pradeep Tamta ji. These hon. Member are coming from the State of Uttarakhand.

Sir, 16 other hon. Members have also contributed to this fruitful discussion. I thank each one of them for their contribution.

Sir, Uttarakhand disaster, as everybody has explained, is a disaster which is unprecedented, and which is beyond all imaginations. The rescue and relief operation was done under extremely hostile conditions, inclement weather and difficult terrain. Fighting against all odds, we were able to rescue 1,35,000 persons to safer places within a short span of time. This is something which we should admire and, in fact, recognize.

Sir, this massive operation is the largest operation in such heights under inclement weather and difficult terrain. It is a remarkable feat. There is no doubt about that. This is a landmark operation under such conditions and it is a world record that is being acknowledged by the world community at large.

Before I start my speech, I wish to pay homage to the known and unknown persons who have lost their lives in this harrowing disaster. The Indian Air Force, the Indian Army, ITBP, NDRF, the Border Roads Organisation, the Armed Forces Medical Services, NGOs, etc. have done commendable role in the rescue and evacuation operations.

Sir, you know that 20 personnel of Indian Air Force as well as ITBP and NDRF personnel have sacrificed their lives in the tragic helicopter accident. You must understand that. Those people have done a commendable job during this rescue operation. Their valour, their commitment and their courage will be long remembered. I salute them for this.

Sir, the solidarity of the people is praiseworthy. In such a colossal disaster, people from all sections of society, forgetting their differences and cutting across political affiliations, came together to save their brothers. It was a Herculean task; it was a stupendous task. The world over the rescue as well as the evacuation operations were praised by one and all. It was a collective action. The Union Government, the State Government, Ministries, Departments and other agencies have put in their efforts in these rescue and evacuation operations. There was remarkable coordination in the rescue and relief operations, leaving no room for any major complaint as such.

Before I come to reply to the significant questions posed by the hon. Members, I draw the attention of this august House to the alarming trend of disasters which are taking place globally. We all know that disasters are taking place at an alarming proportion. A study by the Centre for Research on Epidemiology of Disasters, an organisation which has got direct collaboration with the World Health Organisation, indicates that in the first decade of the 20th century, there were only 73 disasters globally. Now, when it comes to the question in the first decade of the 21st century, the disasters have gone up to 4495. This is an alarming global trend and this is to be seriously addressed by each and everyone who is present here and also by those who are outside this House.

What are the reasons for increase in disasters? The reasons could be many. There will be pressure of population, interference of man with nature, global warming and as we all know climate change has also contributed to a great extent for such disasters globally. It is a fact that disasters cannot be prevented altogether. But, we will be able to reduce the risk, impact and severity of disasters using modern technology, timely mitigation measures, constant training and capacity building, etc. In such a situation what is required is the involvement of the community in a bigger way. Then only will we be able to mitigate or reduce the intensity or severity of these calamities. This must be a continuous ongoing process.

I come to the question of Uttarakhand disaster. We all know and Maharaja knows better that the Uttarakhand calamity occurred two weeks before the monsoon set in over there. Uttarakhand received rainfall of 385.1 mm during the period from 1st June to 18th June 2013. This is against the normal rainfall of 71.3 mm and in excess by 440 percentage points; that is, five times more than the normal rainfall Uttarakhand receives. From 16th June to 18th June, it was extremely heavy rain over there. It was torrential rainfall over there. That was the condition in Uttarakhand immediately after the disaster had taken place.

A question has been raised whether the State Government has done anything after this disaster had taken place. As Smt. Mala Rajya Laxmi Shah has already pointed out, this is no time for us to indulge in blame game and we should appreciate what the State Government has done during such a calamity. I wish to inform this august House that in all such calamities the first responder will be the State Government. In this case also, on receiving the Indian Meteorological Department warning, the State Government issued advisories to all the concerned agencies; district and police administration. Announcement was made by the police at Kedarnath, Rambada, Gaurikund, alerting the general public about the disaster. The district administration stopped further movement of pilgrims. Paying heed to the announcement, a

good number of pilgrims halted at Rishikesh – hon. Maharaja knows about it.

On 16th June itself, the State Government requisitioned the services of ITBP, Army, Indian Air Force, NDRF, etc. A concerted effort of these forces and the local civil officials, NGOs, etc., could evacuate more than 1.35 lakh people in the shortest possible time. That is a record.

Sir, if I do not make a mention of the great services rendered by our Indian Army, Indian Air Force as well as our paramilitary forces, that will be a wrong thing on my part. I would like to make a mention of the services rendered by them. You all know that the Indian Air Force has done a heroic job. You will not believe that for the first two days, nobody could take off an aircraft or a helicopter for rescue operations. Against all odds, our daring and adventurous pilots, risking their lives, took off their helicopters and landed along the banks of the gushing river. They rescued 38,700 persons and 3,470 sorties have been carried out by them. That is an adventurous feat on their part. You all know that Indo-Tibetan Border Police Force guard our borders in Uttarakhand. The ITBP has rescued the largest number, 33,000 persons from difficult terrains. That is also a record.

Coming to the question of State Civil Aviation Department, they have also done their job. They rescued 13,000 people. Hon. Members know that wherever the National Disaster Response Force has been deployed, the State Government has been able to obtain the service promptly. The kind of adventure and the kind of commitment that they have shown in the past is commendable. They have rescued 9,500 persons. The Nehru Institute of Mountaineering in Uttarkashi, about which some of the hon. Members have already made a mention, was able to rescue 6,500 persons. It is not a small thing.

All the hon. Members were mentioning about the relief camps. I would like to tell that 69 relief camps had been set up for 1,51,080 persons. Some camps, as you all know, are still running for local residents. Food, medicine, kerosene, blankets and other essential commodities or items were supplied either by way of air-dropping or by land.

A Missing Persons Cell, that is to be admired, was set up in the capital of Uttarakhand. It was working in the most professional manner. All the scientists, officials as also the NGOs, who had gone over there, saw for themselves how it was working and they were all in praise of this Missing Persons Cell. You all must bear this in mind.

Sir, a sum of rupees five lakh has been declared to be given to the next of the kin of the dead or feared to be dead or missing. The next of kin of 113 dead persons and 818 missing persons have been granted *ex gratia* so far. The rest of the people will also be given money. Whenever we get a clearance certificate or verification certificate from the concerned State Government. Immediately on receiving that, we will be paying the *ex gratia* amount to the tune of rupees five lakh to the next of the kin of the deceased or missing persons. In this amount of rupees five lakh, rupees two lakh are being given by the hon. Prime Minister from the Prime Minister National Relief Fund, Rs. 1.5 lakh are coming from National Disaster Response Fund and Rs. 1.5 lakh are coming from the kitty of the State Government.

Sir, every hon. Member was asking about the road connectivity. Border Roads Organisation and PWD have to reconstruct 1,956 roads which are totally destroyed because of the flash floods and fury of the nature. Of these, 1,681 roads have been opened for vehicular traffic. I do not claim or say that pucca roads have been constructed over there. No, it is not possible. Still heavy rain is going on there, inclement weather is there and climate is very bad. Since adverse climatic conditions are prevailing over there, it is not possible to construct pucca roads, but temporary roads have been constructed over there. Normal vehicular traffic has been disrupted on 271 roads. We are seized of the matter. The mule tracks are also to be reconstructed, about which Maharaja was telling me yesterday. The work of reconstruction of mule tracks as well as foot tracks is hampered due to heavy monsoon as also recurring landslides. Time frame has been fixed for BRO and PWD by the Government of India and the State Government for opening of mule tracks, jeepable and motorable roads in some major sectors.

Coming to the question of power supply, in 3,758 habitations, power supply was totally disrupted due to the disaster. Normal power supply was restored in 3,741 habitations; 17 habitations are without normal electricity still. We have alerted the State Government. The State Government is doing its best, but because of the inclement weather, it is not possible for them to provide electricity to the rest of the habitations.

Coming to the question of drinking water, drinking water supply has been disrupted in 968 habitations. It has been restored in 950 habitations; eighteen habitations are without water supply and that is a major matter. We have taken up the matter with the State Government to provide water as early as possible. They have reported back that because of the difficult terrain and inclement weather, it is not possible for them to provide water over there.

Coming to the communication network, you all know that immediate point-to-point communication by telephone was established in Kedarnath, Badrinath and Harsil. More than 100 satellite phones, somebody has been referring to the satellite phones, have been provided to various Central and State Government agencies immediately after the disaster.

Coming to the question of tourism, which is the mainstay and the backbone of the people over there, in order to augment the livelihood of the people, Uttarakhand Tourism is planning to conduct a study – that is exactly what everybody was, in fact, informing the House – on carrying capacity of various tourist destinations in the State. Uttarakhand Tourism is also planning to evolve regulation, registration system to control tourists' movement with biometric support at all important points. This was one demand raised by the hon. Members. It is also planned to ask the Tour Operators to get the tourists insured before entering Uttarakhand.

Sir, I have contacted the Minister of Tourism the other day. He has sanctioned an amount to the tune of Rs. 100 crore as a special package for the development of tourism infrastructure over there.

Now, I am coming to the services being rendered by the Union Government immediately after getting the information about this gruesome disaster. Sir, the Government of India has promptly mobilised all the Ministries and agencies to supplement the efforts of the State Government. I have already mentioned about the services being rendered by the Army, Indian Air Force and the Paramilitary forces in this great crisis.

The National Crisis Management Committee, you all know, has coordinated all the efforts with the Central Government agencies in concert with the State Government. The hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh as also the Chairperson of the UPA Shrimati Sonia Gandhi have paid visit to Uttarakhand on 19th June itself. The Prime Minister on reaching over there announced an amount to the tune of Rs. 1,000 crore to the hapless people of Uttarakhand. The hon. Home Minister Shri Sushilkumar Shinde, who is sitting here, visited Uttarakhand twice – on 22nd June and on 28th June. He has gone over there to have a special meeting with the hon. Chief Minister of Uttarakhand as also senior officers there. He reviewed the relief and rehabilitation activity over there. Although he is my senior, I know that what he has done from the Home Ministry's side. Throughout the crisis, he was the person who was monitoring the activities, while sitting in the office in North Block.

Sir, in view of the magnitude of the calamity, a Cabinet Committee under the hon. Prime Minister has been constituted, we are all aware of that, for providing broad guidelines for expeditious rehabilitation and reconstruction. The Inter-Ministerial Group under the Cabinet Secretary is drawing up a time-bound action plan for reconstruction of Uttarakhand.

Sir, a member of NDMA, who was the former Secretary of the Home Ministry, has been specially deputed to go over there and coordinate the activities of the State Government and Union Government in a perfect manner. I would like to make it clear that his service was commendable.

Sir, the Government of India supplemented the efforts of the State Government with 80 doctors, 11 psychiatrists and public health team with required equipments.

Another important thing which I would like to place on record is this. It is commendable that there has not been any outbreak of epidemic or infectious disease despite the death of numerous people and animals. That is also a record. An inter-ministerial team has been sent by no less a person than our hon. Home Minister, who is sitting here. They have visited Uttarakhand to make an on the spot assessment of the loss over there. The team has submitted its report. It was discussed in the Inter-Ministerial group led by the Secretary, Ministry of Home Affairs. It now has gone to the High Level Committee; that High Level Committee is led by no less than a person than our Agriculture Minister Shri Sharad Pawar, wherein our hon. Home Minister, Finance Minister and Vice-Chairman of the Planning Commission are the other Members. They have assessed the gravity of the situation and from the National Disaster Relief Fund, they have announced an amount to the tune of Rs. 1,187.87 crore to the State of Uttarakhand.

Sir, the Cabinet Committee under the Chairmanship of our Prime Minister is examining long-term rehabilitation of Uttarakhand. You all know that the Planning Commission is the nodal department to coordinate the Central Government assistance to State for medium and long-term rehabilitation and reconstruction of infrastructure as well as for the livelihood package. An external assistance package is being worked out –it is for the information and benefit of the hon. Members from Uttarakhand, by the State Government with the support of the World Bank, Asia Development Bank and International Fund for Agriculture Development with the coordination of Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance.

Sir, a mention has been made by some Members about the Indian Meteorological Department's warning at the time of this crisis. We all know that the main responsibility of the IMD is forecasting the weather. That warning is of general nature and you all must understand that. Some misunderstandings have been created that IMD has given a warning about this sort of flash flood and disaster and all that. No such information was given by the Indian Meteorological Department. I had a discussion with the scientists of the Department yesterday and day before. They gave me information about that general warning of heavy to very heavy rain on 15th and 16th of June, 2013. Sir, immediately after getting information, as I mentioned earlier, the State Government alerted all agencies to be on their toes and they have done their maximum at that particular point of time. Sir, monsoon as I said, set in Uttarakhand, two weeks early. Pilgrims had already reached higher levels before warning could be issued. When the catastrophe struck on 16th and 17th, it was humanly impossible to evacuate a single person because of continuous inclement weather and difficult terrain.

Sir, we need to improve and we need to examine the technical feasibilities of enhancing our capabilities and scientific organisations. In this connection, I would like to say that the Ministry of Earth Sciences has decided to go in for Mountain Meteorological Services and Integrated Himalayan Meteorological Service. Under this project, nine Doppler weather radars are proposed for the fragile Himalaya region alone. The IMD has already prepared a comprehensive proposal for about Rs. 360 crore for Integrated Himalayan Meteorological Programme.

Sir, I made a mention about the Missing Persons Cell. This Missing Persons Cell – is in fact functioning in a most professional manner. I already mentioned about it. They collected details from various districts, States sources like E-mails, websites, SMS, police department, call data from different towers, between 14th and 19th June, 2013, from and to pilgrims mobiles were traced for cross-checking last calls with date, time and location. What all information is there with the Missing Persons Cell, is an accurate information. We are collecting more information from the centres. We will have fool-proof information about the number of persons who have lost their lives or are missing. The information as on 27th July, 2013 reflects 5,359 persons as missing which includes 4,421 pilgrims from other States and 938 local residents. 91 Nepali citizens are also missing. We are very seriously collecting the details about the missing persons. About 396 bodies have been cremated. ...(*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : उन्हें कब तक मिसिंग माना जायेगा? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : उन्हें कब तक मिसिंग माना जायेगा। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि मंत्री जी खड़े हैं। ...(व्यवधान) उन्हें कब तक मिसिंग माना जायेगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : He is talking about the death certificates.

...(*Interruptions*)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I will come to that....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is coming to that. Please have patience.

...(*Interruptions*)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: About 396 bodies have been cremated by the police with full honour and rituals after DNA sampling. Some bodies were cremated by the villagers because de-composed bodies were scattered here and there. A number of bodies were washed in the gushing waters. Many are presumed to be buried under debris.

Coming to the question of national disaster management, every Member, almost all the Members have in fact, expressed their apprehensions....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, he has a very relevant question.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: What is it about?

MR. CHAIRMAN: It is regarding issuing of the death certificates to the missing persons.

...(*Interruptions*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : एक चीज और है ...(व्यवधान) उनके कारोबार का विषय है या कोई भी चीज है जैसे मकान वगैरह हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं वही कह रहा हूं।

â€¦(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): इसमें एक विषय और है। उत्तराखंड सरकार डेथ सर्टीफिकेट जारी नहीं कर रही। ...(व्यवधान) वह कहती है कि संबंधित राज्य सरकार डेथ सर्टीफिकेट देगी। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उत्तराखंड सरकार डेथ सर्टीफिकेट नहीं दे सकती है, वह तो संबंधित राज्य सरकार ही देगी।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, they have a question regarding the issuance of a death certificate for the persons who are missing.

...(*Interruptions*)

श्री राधे मोहन सिंह (गाज़ीपुर): सभापति महोदय, मिसिंग वाला मामला हर जगह का है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, मंत्री जी ने बात सुन ली है। वे उसका जवाब देंगे।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Could you throw some light on this?

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. He is coming to that. Please be seated.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप बैठिये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने आपकी भावना समझ ली है।

â€¦(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, I can collect the information and provide to the Members. I will pass it on to the hon. Members.â€¦ (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is a technical question. When will the persons who are missing, be treated as dead? The persons who are missing, when will the Government issue death certificates to them? That is the question.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Inquiry is still going on by the State Government, the Police and the local authorities. As soon as all information is collected, we will direct the State Government to carry out this information and do it quickly within two, three months....(*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Who will issue the death certificate?...(*Interruptions*)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : यदि गुजरात, राजस्थान का आदमी मिसिंग है, तो उसकी इन्फोर्मेशन पुलिस में दी जायेगी। ...(व्यवधान) यह इन्फोर्मेशन दी जायेगी कि यह आदमी यात्रा पर गया था। ऐसी मिसिंग रिपोर्ट करायी जायेगी, तो उसके बाद वे पुलिस से वेरीफाई करेंगे तभी उसको मिसिंग माना जायेगा। वे ऐसे ही सर्टीफिकेट नहीं मानेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी, सदस्यों की भावना यह है कि उनको कम्पेशनेट ग्राउंड पर, अनुकम्पा के आधार पर सहायता दी जाये।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी ने बता दिया है।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हां, समझ गये। मंत्री जी बता रहे हैं कि जब सूचना आ जायेगी, तब कार्रवाई करेंगे।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He has the answer now. Please be seated. He will now give the answer.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN: Let him speak. Let the Minister speak.

श्री सुशीलकुमार शिंदे : वे दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकरण में कई गलत लोग भी आ सकते हैं इसलिए हमें पूरी इन्वेस्टीगेशन करके पाच लाख रुपये देने पड़ते हैं। हम स्टेट गवर्नमैंट को फिर बोलेंगे, डायरेक्शन दे देंगे कि जल्द से जल्द जितने मिसिंग हैं, उन सबके रिकार्ड एक बार फिर मंगवा लीजिए, क्योंकि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यह बहुत क्लीयरली बताया। इतना ही नहीं, डी.एन.ए. रिपोर्ट भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। आज भी उधर मौसम खराब है। सभापति जी आप वहां के हैं, आपको पता है कि वहां हेलीकॉप्टर नहीं जाते हैं, कितने लोग डेबरीज के नीचे दबे हुए हैं, यह भी अभी पता नहीं है। जैसे-जैसे बारिश कम हो जाएगी, वैसे-वैसे वहां खुदाई हो जाएगी।

सभापति जी, आपको भी पता है कि खुदाई करने की मशीन जे.सी.बी. ऑडिनरी हेलीकॉप्टर- 17 से नहीं भेजे जा सकते हैं। इसके लिए 126 जो स्पेशल प्लेन है, उसे मंगवाया गया है और पार्ट्स डिस्एसेम्बल करके, वहां केदारनाथ पर जाकर एसेम्बल कर रहे हैं और खुदाई का काम कर रहे हैं। यह काम चालू है। आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी सदस्यों की चिंता यह है कि कम्पेनसेशन के लिए वे मान लेंगे कि मर गया है, पर उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो जाए और उनके बच्चों को कम्पेनसेटरी ग्राउंड पर नौकरी मिल जाए।

â€¦(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिन्दे : यदि आज भी डेबरीज के नीचे बॉडी मिलती है, तो हम उसका डी.एन.ए. कलेक्ट करते हैं ...(व्यवधान) और जहां भी उसके ऊपर एक-आधा निशान मिला है, तो उस निशान के आधार पर हम स्टेट को लिखते हैं और उससे टैली हो गया, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी बता रहे हैं, सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Let the Minister speak.

*(Interruptions) â€¦**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): ...(व्यवधान) आप कहें, तो मैं लिखकर दे देता हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हाँ, आप लिखकर दे दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I am coming to that point. There is no need to wait for seven years. The Registrar General of India has given a detailed circular. Death certificate will be issued by Uttarakhand officers based on the inquiry report from the respective States. That is all. There ends the matter.

MR. CHAIRMAN: Okay. That is done.

SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN: Coming to the question of the National Disaster Management Authority, disaster preparedness, and the Disaster Management Act of 2005, every single Member has mentioned this point. Everybody is apprehensive of the functions being carried out by NDMA.

In this connection I wish to inform the august House that in the year 2011 a task force was constituted by Government of India to study the functioning of the National Disaster Management Authority as also the National Disaster Management Act of 2005, as also the disaster preparedness of this country. The task force has already submitted its report last April and we are examining the report. We will definitely be coming out with very positive steps in this connection. The task force recommends restructuring of NDMA and amending the Disaster Management Act, apart from other matters.

Some Members have expressed concern about the fragile ecology and environment of Uttarakhand. This is a very serious matter and I fully share the sentiments of the hon. Members about the ecologically fragile nature of Uttarakhand. The Government of India is seriously seized of the matter. The Central and the State Governments in fact have sensitized all the agencies to involve the stakeholders in preservation of ecological balance, forest cover and planned development.

21.39 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

The revered Himalayas is one of the youngest mountain ranges on the planet. It is home to one of the richest

biodiversities of the world. It is the 'water tower' of the world. It is very critical for 40 per cent of humanity. Therefore, we are sensitizing the State Government and we are sensitizing all the Ministries. The Environment Ministry has been contacted. Every other Department has been alerted and sensitized. They have been apprised of the importance of the ecology of the fragile Himalayas.

Coming to the question of Char Dham, we all know that Char Dham consist of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. Puja was unaffected at the three Dhams except Kedarnath. It has been decided that Kedarnath temple will also be restored and daily puja will be commenced on 11th September, 2013.

Coming to the foot bridge on River Mandagini at Shri Kedarnath Ji has been constructed. It is planned to be replaced by iron bridge by 10th September 2013. The bridge on Mandagini at Rambada is also expected to be completed by 10th September 2013. The road connectivity up to Soneprayag has been restored. The pedestrian route from Soneprayag to Rambada is nearing completion. The pedestrian route from Rambada to Kedarnath is also to be restored by 10th September 2013. As I said, the regular pooja at Kedarnath will be resumed on 11th September 2013.

Sir, as I have already mentioned, the primary responsibility in any disaster lies with the State Government. The Central Government provides necessary logistic and financial support to the State Government. As disasters are becoming more and more complex due to large ecological global environmental changes, the disaster management, as all the hon. Members shared the view, needs continuous upgradation. I wish to mention that the response to the Uttarakhand disaster was tremendous. All, irrespective of the differences, came together to save maximum number of people – 1,35,000 people have been evacuated and rescued. It comes from our observation that we need to further strengthen and augment the disaster management mechanism. The report of the task force is, as I said, under the examination of the Government of India. We will come out with an action plan as early as possible. I place on record my deep gratitude to the hon. Members who have taken part in this discussion. I am sure that the State Disaster Management Plans and the National Disaster Management Plans will take into account the learnings from Uttarakhand so that the systems are improved significantly and the losses due to the natural calamities are reduced to the minimum.

Sir, our dream is to build a disaster-resilient India. That would be the true homage that we can pay to the people who lost their lives in this horrendous disaster.

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up 'Zero Hour'.